न्यू देहली पोस्ट

■ वर्ष 13 ■ अंक 14 रविवार (साप्ताहिक) 13 अप्रैल 2025 ■ पृष्ठ 16 ■ मूल्य 5 रुपये

क्या आईपीएल 2025 से संन्यास लेंगे विराट ?

अंदर विशेष

क्या महुआ मोइत्रा का संसद से निष्कासन गैर क़ानूनी था?
पृष्ठ 3 पर

यूपी के बुलडोजर राज से सुप्रीम कोर्ट नाराज
पृष्ठ 5 पर

ओडिशा में कांग्रेस बीजद की जगह लेने की कर रही तैयारी
पृष्ठ 7 पर

अब पंजाब को नशामुक्त करेंगे केजरीवाल
पृष्ठ 10 पर

एचआईवी फंडिंग में कटौती से तीन मिलियन लोगों की मौत की संभावना
पृष्ठ 11 पर

डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी तो ईरान ने तैनात की मिसाइल
पृष्ठ 15 पर

मुस्लिम समुदाय की स्वायत्ता पर चोट

वक्फ बिल संसद से पास

लोकसभा ने 12 घंटे की लंबी बहस के बाद गुरुवार, 3 अप्रैल को तड़के विधेयक पारित कर दिया। कुल 288 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 232 ने इसका विरोध किया।

अखिलेश अखिल

आखिरकार वही हुआ जिसकी सम्भावना थी। इंडिया गठबंधन के भारी विरोध के बाद भी मोदी सरकार ने इस बिल को संसद के दोनों सदनों से पास करा लिया। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। उनकी मुहर लगेगी और फिर इस बिल के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस कानून के बाद देश के मुसलमानों की थाती को तार -तार कर दिया गया। इस कानून का का भारतीय समाज से लेकर राजनीति पर क्या कुछ असर पडेगा यह तो आने वाले समय में पता चलेगा लेकिन बड़ी बात तो यह है कि संसद में इस बिल का समर्थन करने वाले कई दलों और उनके नेताओं का पाखंड भी सामने आ गया। टीडीपी नेता और आँध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम समाज के सामने नंगे हो गए। उनका मुस्लिम प्रेम ,मुसलमानो के लिए बहुत कुछ करने की बात और सेक्युलर होने का दंभ चकनाचूर हो गया और एक सबसे बड़े पाखंडी नेता के रूप में वे भारतीय राजनीति में अवतरित हो गए।

पिछले आंध्रप्रदेश विधान सभा चुनाव के दौरान उनकी लाज यही मुस्लिम जमात ने बचाई थी। हर जगह रुदाली करने वाले नायडू को सहारा यही मुस्लिम समाज ने दिया था। उम्मीद यही थी कि नायडू की सरकार आएगी तो उनका जीवन धन्य होगा ,उनकी मुसीबतें कम होंगी ,उनके खिलाफ बीजेपी द्वारा चलायी जा रही नीति के खिलाफ जाकर वे उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन नायडू ने कुर्सी मिलते ही अपना रंग दिखा दिया और पलट गए। इस पलटी मार नेता को अपनी कुर्सी चाहिए थी। उन्हें मुस्लिम समाज से अब कोई वास्ता नहीं रह गया था। वे मानते हैं कि अगला चुनाव तो चार साल बाद होने हैं और समय के साथ मुसलमान सब कुछ भूल जायेंगे और फिर से उनके साथ जुड़ जाएंगे। इसमें सच्चाई भी है। लेकिन आगे क्या होगा यह भला कौन जनता है।

नंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हुए हैं। अब उनके चेहरे का नूर ही ख़त्म हो गया है। उनका इकबाल जमींदोज हो गया है। जदयू बचेगी या नहीं या फिर जदयू बीजेपी के पाले में चली जाएगी यह भी नीतीश कुमार नहीं जानते। नीतीश कुमार राजनीति से अब आउट हो गए हैं या यह भी कहा जा सकता है कि उन्हें बीजेपी ने एक रणनीति के तहत आउट कर दिया है। उनकी पार्टी के अधिकतर नेताओं को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है और नीतीश को मुसलमानो का सबसे बड़ा दुश्मन बनाकर उनकी राजनीतिक विरासत को तार तार कर दिया है।

शेष १ पर

अब भारत के रडार पर बांग्लादेश

राजनीतिक डेस्क

बांग्लादेश में पिछले साल भर से जो भी हो रहा था उसे बांग्लादेश का आंतरिक मामला मानते हुए भारत अब तक चुप था लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के चीन दौरे के दौरान दिए गए एक बयान ने भारत में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। खासकर सत्ताधारी बीजेपी और मुख्या विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अब यूनुस के बयान को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि भारत बहुत जल्द ही बांग्लादेश के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। संभव है कि बांग्लादेश के भूक्षेत्र को लेकर भी भारत कोई बड़ा एक्शन ले सकता है।

बता दें कि यूनुस ने पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों, जिन्हें 'सेवन सिस्टर्स' के नाम से जाना जाता है, को लैंडलॉक्ड बताते हुए एक ऐसा संकेत दिया, जिसे भारत ने अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी माना। इस बयान की गूंज न केवल राजनयिक हलकों में सुनाई दी, बल्कि भाजपा और कांग्रेस जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों ने भी इसे गंभीरता से लिया। दोनों दलों ने न सिर्फ यूनुस की टिप्पणी की कड़ी निंदा की, बल्कि 'चिकन नेक' कॉरिडोर के रणनीतिक महत्व को बचाने और बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए कड़े कदमों के सुझाव भी दिए। यूनुस का यह बयान, जिसमें उन्होंने चीन को बांग्लादेश में निवेश और व्यापार के लिए आमंत्रित किया, भारत के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। त्रिपुरा की प्रभावशाली क्षेत्रीय पार्टी टिपरा मोथा के नेता प्रद्योत देबबर्मन ने इस मुद्दे पर सबसे साहसिक रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि चिकन नेक की भौगोलिक कमजोरी को दूर करने के लिए इंजीनियरिंग परियोजनाओं में अरबों रुपये खर्च करने की बजाय बांग्लादेश को खंडित कर देना चाहिए। उनका तर्क है कि इससे पूर्वोत्तर भारत को समुद्री पहुंच मिलेगी, जो क्षेत्र की आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा के लिए जरूरी है।

शेष १ पर

क्या मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे पीएम मोदी ?

राजनीतिक डेस्क

बीजेपी का मार्गदर्शक मंडल क्या है और वह क्या कुछ करता है यह आजतक कोई नहीं जानता। और बीजेपी के जो बड़े नेता मार्गदर्शक मंडल में भेजे गए हैं ,वे क्या करते हैं और क्या कहना चाहते हैं। इसकी जानकारी भी किसी को नहीं है। लेकिन मोदी जब से केंद्र की राजनीति कर रहे हैं ,मार्गदर्शक मंडल की चर्चा होती है। और यह सब इसलिए कि इस मंडल की स्थापना उन्होंने ही की है। उन्होंने सत्ता में आते ही अपनी पार्टी बीजेपी के लिए एक कानून बनाया कि जिन नेताओं की उम्र 75 साल हो गई है वे अब आराम करेंगे ,चुनाव नहीं लड़ेंगे और सिर्फ पार्टी को सलाह भर देंगे। इसी कानून के तहत बीजेपी के कई नेता जैसे

लालकृष्ण आडवाणी ,मुरली मनोहर जोशी ,शांता कुमार और जाने कितने और भी मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए। अब उनकी राजनीतिक रूप से कोई भूमिका नहीं है। उनकी पूछ तक नहीं होती।

लेकिन प्रकृति का नियम भी तो विचित्र है। जो आया है वह जवान के बाद बूढ़ा भी होगा और 75 साल का भी होगा। पीएम मोदी भी अब इस उम्र के पास पहुँच रहे हैं। वे 17 सितम्बर को 75 साल के हो जायेंगे। तभी यह सवाल उठ रहा है कि सभी बूढ़े नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजने वाले मोदी क्या सितम्बर के बाद जोशी और आडवाणी के साथ खड़े हो जायेंगे ?

इस सवाल का सटीक उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता। हो सकता है संघ के नेताओं के पास इस सवाल के कुछ जवाब हों। यह भी संभव है कि हालिया भागवत और मोदी की मुलाकात में इस पर चर्चा भी हुई हो। लेकिन अभी इसी का सवाल का एक जवाब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने दिया है।

शेष १ पर

राम मंदिर से भी बड़े...

उनकी सेक्युलर छवि को धूमिल कर दिया गया है। बिहार ही नहीं पुरे उत्तर भारत के मुसलमानो को नीतीश कुमार से इस वक्फ बिल को लेकर बड़ी आस लगी थी। लेकिन नीतीश ने मुसलमानो से पलटी मारकर बीजेपी का साथ दिया। वैसे बीजेपी के साथ तो वे सरकार लम्बे समय से चला रहे हैं लेकिन मुसलमानो के मसले पर वे हमेशा गंभीर और सतर्क रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने सब कुछ खो दिया। मुसलमानो का विश्वास उन्होंने तोड़ा और राजनीति से भी आउट हो जायेंगे। बिहार में जदयू के पक्ष में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट पड़ते रहे हैं। लेकिन अब नीतीश को मुसलमान वोट करेंगे इसका दावा कौन करेगा ? अब संसद में क्या कुछ हुआ और किसने क्या कहा इस पर नजर डालने की जरूरत है। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से पास होने पर विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक, जनविरोधी और राजनीति से प्रेरित बताया है। कपिल सिब्बल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार के पास लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत था, लेकिन यह बिल देश में विभाजन को दर्शाता है।उन्होंने बताया कि वोटिंग में 128 पक्ष में और 94 खिलाफ वोट पड़े, जिससे साफ है कि बड़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया। सिब्बल ने कहा कि इसका असर बिहार जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों पर पड़ेगा, जहां विपक्ष को फायदा हो सकता है। उन्होंने इसे समाज को बांटने वाली राजनीति का हिस्सा बताया और कहा कि यह बिल गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दों को हल नहीं करेगा।उनके मुताबिक, यह एक राजनीतिक चाल है, जिससे विवाद बढ़ेगा और सरकार को लगता है कि इससे उसे फायदा होगा। सिब्बल ने चेतावनी दी कि यह देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है।

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे विपक्ष की नैतिक जीत करार दिया। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा में बिल के खिलाफ 35 वोटों का अंतर था और राज्यसभा में अंतर कम था।सिंघवी ने इसे जनादेश के खिलाफ बताया और कहा कि सरकार ने अपने बहुमत का दुरुपयोग करके इसे जबरदस्ती थोपा है।उन्होंने दावा किया कि अगर बिल को कोर्ट में चुनौती दी गई, तो इसके असंवैधानिक होने की पूरी संभावना है, खासकर संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत। सिंघवी ने यह भी कहा कि यह बिल मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता को नष्ट करता है और समाज में अविश्वास पैदा करेगा।उनके मुताबिक, यह जनता के मूड के खिलाफ है और इसमें व्यापक समर्थन की कमी है।

राजद नेता मनोज झा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसी संसद में पहले किसान कानून भी पास हुए थे, जिन्हें बाद में वापस लेना पड़ा।झा ने सरकार पर बहुमत के अहंकार का आरोप लगाया और कहा कि संख्या बल होने का मतलब यह नहीं कि हर ज्ञान सरकार के पास ही है।

उन्होंने इसे गैर-जरूरी और विभाजनकारी बताया। झा ने कहा कि राज्यसभा में सरकार का बहुमत बहुत मजबूत नहीं था, फिर भी उसने इसे पास करवाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जनता की नाराजगी को दूर नहीं किया गया, तो इस बिल का हश्र भी किसान कानूनों की तरह हो सकता है। झा ने सरकार से आत्ममंथन करने और संजीदगी दिखाने की अपील की।

लोकसभा की ही तरह राज्यसभा में सत्तापक्ष यानी एनडीए एकजुट रहा और भाजपा व सभी घटक दलों के सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट किया। दूसरी ओर 'इंडिया' ब्लॉक की सभी पार्टियों ने बिल के खिलाफ वोट किया। तेलंगाना की मुख्य विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति ने बिल का विरोध किया। परंतु ओडिशा की मुख्य विपक्षी पार्टी और एक समय भाजपा की सहयोगी रही बीजू जनता दल ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी नहीं किया। उसने सबको अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा। राज्यसभा में उसके सात सांसद हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अपने भाषण में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने, 'हमने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तुलना में वक्फ बिल को लेकर कहीं ज्यादा गंभीरता दिखाई। यह बिल पार्टी इंट्रेस्ट का नहीं है, यह नेशनल इंट्रेस्ट का विषय है। इसलिए मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। विषय को डिरेल नहीं करना चाहिए'। नड्डा ने कहा कि 31 सदस्यों की जेपीसी ने इस बिल पर विचार के लिए 36 बैठकें कीं और दो सौ घंटे तक चर्चा की। उन्होंने कहा, 'बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है। कहीं कुंभ मेला दिख रहा है। बिहार का इलेक्शन दिख रहा। कहीं एअर इंडिया बिक गया। कहीं केरला का सिनेमा आ गया। ये सब चर्चा को डिरेल करने की कोशिश है'।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 गुरुवार को ही लोकसभा में पारित हो गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को विधेयक सदन में पेश किया था, विधेयक को 288 के मुकाबले 232 मतों से सदन की मंजूरी मिल गई। इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए सदन की बैठक रात लगभग दो बजे तक चली। इसके अलावा, मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 का निरसन करने वाला मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 भी सदन में ध्वनि मत से पारित हो गया।

चर्चा के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार के लिए जब किरेन रिजिजू ने प्रस्ताव रखा, तो विपक्ष के कुछ सदस्यों ने मत विभाजन की मांग की। इसके पक्ष में 288 और विरोध में 232 मत पड़े। हालांकि, लॉबी क्लीयर करने के बाद कई सदस्यों को सदन में दाखिल होने देने को लेकर विवाद भी हुआ। वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों के प्रावधान को लेकर रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन पर भी मत विभाजन हुआ। उनका संशोधन 231 के मुकाबले 288 मतों से अस्वीकृत हो गया। विपक्ष के अन्य सभी संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित होने की निंदा की और ऐलान किया कि डीएमके इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। तमिलनाडु विधानसभा में सीएम स्टालिन ने कहा, "तमिलनाडु लड़ेगा और इस लड़ाई में उसे सफलता मिलेगी।" लोकसभा में विधेयक पारित होने के विरोध में डीएमके विधायकों ने विधानसभा सत्र के दौरान काली पट्टियां बांधीं।

सीएम स्टालिन ने सदन को याद दिलाया कि 27 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि यह धार्मिक सद्भाव को कमजोर करता है और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने कहा, "भारत भर में अधिकांश राजनीतिक दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। फिर भी, इसे लोकसभा में पारित कर दिया गया, जो अत्यधिक निंदनीय है।

सीएम स्टालिन ने आगे कहा, हालांकि यह सदन से पारित हो गया है, लेकिन इसके खिलाफ बड़ी संख्या में वोटों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।" मुख्यमंत्री ने कहा कि 232 सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया, यह रेखांकित करते हुए कि यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। उन्होंने कहा, "विपक्ष और भी मजबूत हो सकता था। इस कानून को पूरी तरह से वापस लिया जाना चाहिए।"

लोकसभा ने 12 घंटे की लंबी बहस के बाद गुरुवार, 3 अप्रैल को तड़के विधेयक पारित कर दिया। कुल 288 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 232 ने इसका विरोध किया। व्यापक विरोध के बावजूद, विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए सभी संशोधनों को ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। बहस के दौरान, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने विधेयक का बचाव करते हुए दावा किया कि इसे अल्पसंख्यक समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है।

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि इस विधेयक को जबरन पारित किया गया। हमारी पार्टी का रुख स्पष्ट है। यह विधेयक संविधान पर एक हमला है। वक्फ संशोधन बिल सिर्फ साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए है। यह बीजेपी की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। ये देश को एक सर्विलांस स्टेट बना रहे।बैठक में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार देश को रसातल में ले जा रही है, जहां संविधान केवल कागजों पर रह जाएगा। उन्होंने कहा कि 'एक देश, एक चुनाव' विधेयक भी संविधान का उल्लंघन है। हम इस कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। सोनिया ने कहा किअर्थव्यवस्था बुरी हालत में है। चीन से इम्पोर्ट काफी बढ़ा है।

अब भारत के रडार...

प्रद्योत ने 1947 में चटगांव बंदरगाह पर भारत के दावे को छोड़ने को ऐतिहासिक भूल करार दिया और इसे सुधारने की वकालत की। उनके इस बयान ने क्षेत्रीय नेताओं के बीच एक नई बहस को जन्म दिया है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यूनुस के बयान को भारत के लिए खतरे की घंटी बताया है । उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश जानबूझकर चीन को इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने के लिए आमंत्रित कर रहा है, ताकि भारत को रणनीतिक रूप से घेरा जा सके। खेड़ा ने कहा कि यह कदम पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में तत्काल कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाने की मांग की, साथ ही बांग्लादेश के इस रवैये को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौती करार दिया।

यूनुस के बयान ने भारत में एकजुटता के साथ-साथ आक्रोश को भी जन्म दिया है। भाजपा और कांग्रेस, जो आमतौर पर एक-दूसरे के खिलाफ खड़े रहते हैं, इस मुद्दे पर एक स्वर में बोलते नजर आए। चिकन नेक कॉरिडोर, जो पूर्वोत्तर भारत को शेष देश से जोड़ने वाला एकमात्र संकरा रास्ता है, लंबे समय से रणनीतिक चिंता का विषय रहा है। अब यह सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश को तोड़कर या वैकल्पिक मार्ग बनाकर इस समस्या का समाधान संभव है? यह विवाद न केवल भारत-बांग्लादेश संबंधों को प्रभावित करेगा, बल्कि क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी के संदर्भ में भी नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को भारत में शामिल करना चिकन नेक की समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। रंगपुर डिवीजन, जो भारत के उत्तर बंगाल और असम के पास स्थित है, पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। यदि रंगपुर को भारत में शामिल किया जाता है, तो चिकन नेक कॉरिडोर की संकीर्णता खत्म हो जाएगी और यह कॉरिडोर कम से कम 150 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा। इससे पूर्वोत्तर भारत की मुख्य भूमि से कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इसी तरह, चटगांव डिवीजन के कुछ हिस्से, जो त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा से सटे हैं, भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चटगांव बंदरगाह तक पहुंच से न केवल समुद्री व्यापार बढ़ेगा, बल्कि क्षेत्र की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने यूनुस के बयान को भड़काऊ करार देते हुए कहा कि इसके पीछे एक गहरी रणनीति और दीर्घकालिक एजेंडा छिपा है। सरमा ने सिलिगुड़ी कॉरिडोर, जिसे 'चिकन नेक' के नाम से जाना जाता है, की भेद्यता पर प्रकाश डाला और इसे मजबूत करने के लिए वैकल्पिक उपायों की वकालत की। उन्होंने सुझाव दिया कि चिकन नेक के नीचे और आसपास मजबूत सड़क और रेल नेटवर्क विकसित किया जाए, ताकि पूर्वोत्तर भारत का संपर्क मुख्यभूमि से कभी न टूटे। सरमा ने इस खतरे को हल्के में न लेने की चेतावनी दी और केंद्र से ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।

क्या मार्गदर्शक मंडल...

उन्होंने कहा है कि ''जब पिता जीवित हों तो उत्तराधिकारी पर बात करना ठीक नहीं है। यह सब तो मुगलों के काल में होता था। मोदी के साथ आरएसएस मुख्यालय गए फडणवीस ने नागपुर में संवाददाताओं से कहा, "उनके (मोदी के) उत्तराधिकारी की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। वह (मोदी) हमारे नेता हैं और आगे भी बने रहेंगे।"

मोदी के उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर आरएसएस के पसंदीदा माने जाने वाले मुख्यमंत्री ने मुगलों पर निशाना साधते हुए सवाल को टाल दिया। उन्होंने कहा, "हमारी संस्कृति में, जब पिता जीवित हो, तो उत्तराधिकार के बारे में बात करना अनुचित है। यह मुगल संस्कृति है। इस पर चर्चा करने का समय नहीं आया है।"जाहिर है फडणवीस ने मोदी की सेवानिवृति को ख़ारिज कर दिया है। लेकिन संभवतः फडणवीस को यह बात समझ में नहीं आई कि मोदी सरकार ने पार्टी के दो प्रमुख वरिष्ठ नेताओं - लालकृष्ण आडवाणी और एम.एम. जोशी को उम्र के कारण "मार्गदर्शक मंडल" के जंगल में भेज दिया है।

पीएम मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद भाजपा के पुराने नेताओं को किनारे करने के लिए खुद ही 75 साल की अनौपचारिक सेवानिवृत्ति की उम्र लागू कर दी थी। राज्यसभा सांसद राउत ने इससे पहले मुंबई में संवाददाताओं से कहा था कि मोदी "अपनी सेवानिवृत्ति योजना पर चर्चा करने" के लिए आरएसएस मुख्यालय गए थे। राउत ने दावा किया, "आरएसएस के बारे में मेरी समझ में दो बातें हैं। पहली, संगठन देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है; और दूसरी, मोदीजी का समय खत्म हो चुका है और वह खुद बदलाव चाहते हैं।" मोदी रविवार को नागपुर गए थे।

बता दें कि प्रधानमंत्री के तौर पर अपने करीब 11 साल के कार्यकाल में मोदी की आरएसएस मुख्यालय की पहली यात्रा को व्यापक रूप से संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ संबंधों को सुधारने और अपनी पसंद के नए भाजपा अध्यक्ष के लिए वैचारिक अभिभावक की मंजूरी हासिल करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। वरिष्ठ आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि उन्हें "(मोदी के) प्रतिस्थापन के बारे में किसी बातचीत" की जानकारी नहीं है।

पिछली बार मोदी की संभावित सेवानिवृत्ति पिछले साल के आम चुनाव से पहले सार्वजनिक चर्चा का विषय बनी थी, जब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आग भड़काई थी। केजरीवाल ने शरारती ढंग से दावा किया था कि अगर मोदी दोबारा चुने गए तो 75 साल की उम्र में अपने भरोसेमंद अमित शाह के पक्ष में प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे।बीजेपी नेतृत्व को इस दावे को आक्रामक तरीके से खारिज करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें कहा गया कि अलिखित सेवानिवृत्ति की उम्र मोदी पर लागू नहीं होती।शाह ने कहा था, "मैं अरविंद केजरीवाल और कंपनी और इंडी गठबंधन को बताना चाहता हूं कि उन्हें मोदी जी के 75 साल के होने पर खुश होने की जरूरत नहीं है।"

सकता है कि पीएम मोदी के ऊपर उनके द्वारा बनाये गए मार्गदर्शक मंडल वाला कानून लागू नहीं हो और वे जबतक चाहे पीएम बने रहे या फिर बीजेपी की राजनीति करते रहें लेकिन उनके संभावित उत्तराधिकारियों की चर्चा भी कम नहीं है। कई नेता हैं जो इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि पीएम म यदि की कुर्सी उन्हें मिल सकती है और इसके लिए वे प्रयास भी कर रहे हैं।

गृह मंत्री शाह को लंबे समय से मोदी के "स्वाभाविक उत्तराधिकारी" के रूप में देखा जाता रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल के महीनों में अपने हिंदुत्व के उग्र ब्रांड के कारण एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरे हैं। वे भी पीएम के दावेदार हैं। संघ में भी उनकी पहुँच बढ़ी है और वे संघ के चहेते भी बने हुए हैं। नितिन गडकरी भी पीएम मटेरियल हैं तो शिवराज चौहान भी खुद को किसी से कमजोर नहीं मानते। और अब तो फडणवीस भी बड़े दावेदार के रूप में सामने आये हैं।

वक्फ बिल की लड़ाई में राहुल के सवाल पर मौन सरकार

न्यूज़ डेस्क

संसद में वक्फ बिल पर संग्राम छिड़ा हुआ है। लोकसभा में इस बिल को लेकर 9 घंटे तक वाद -विवाद होता रहा और अंत में यह बिल लोकसभा में पास भी हो गया। अब राज्यसभा की बारी है। बहस जारी है। उम्मीद की जा सकती है कि राज्य सभा में भी यह बिल पास हो जाएगा क्योंकि संख्या बल के हिसाब से यहाँ भी एनडीए की बढ़त है। लेकिन इसी घमासान के बीच राहुल गाँधी ने अमेरिकी टैरिफ और चीन द्वारा हड़पी गई जमीन पर सवाल दाग कर सत्ता पक्ष को मुश्किल में दाल दिया है। राहुल गांधी ने लोकसभा में पूछा कि हमारी जमीन के बारे में और टैरिफ़ के मुद्दे पर क्या करने जा रहे हैं। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का दावा करते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस पड़ोसी देश के साथ संबंध सामान्य होने चाहिए, लेकिन उससे पहले सीमा पर पूर्व की स्थिति बहाल होनी चाहिए और भारत की भूमि लौटाई जानी चाहिए।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ''हमारे साझेदार देश (अमेरिका) ने 26 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है जो हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा, हमारा ऑटो उद्योग, दवा उद्योग और कृषि सभी कतार में हैं।'' उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि वह क्या करने जा रही है।अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 26 प्रतिशत का 'रियायती जबाबी शुल्क' लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से विभिन्न देशों पर शुल्क लगाने की घोषणा करते हुए कहा था, ''भारत हमसे 52 प्रतिशत शुल्क लेता है, इसलिए हम उनसे इसका आधा, 26 प्रतिशत शुल्क लेंगे।'' राहुल गांधी ने चीन के अतिक्रमण का उल्लेख करते हुए दावा किया, ''यह सर्वविदित है कि चीन हमारे 4,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बैठा हुआ है। कुछ समय पहले मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि विदेश सचिव चीन के राजदूत के साथ केक काट रहे हैं।'' उन्होंने आरोप लगाया, ''चीन ने हमारा 4,000 वर्ग किमी क्षेत्र ले लिया, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन केक काटकर उनकी शहादत का जश्न मनाया जा रहा है।''

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ''मेरी जानकारी में यह भी आया है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने चीन को पत्र लिखा है। इस बात की जानकारी हमें चीनी राजदूत ही दे रहे हैं, हमारे अपने लोग नहीं।'' कांग्रेस नेता ने कहा, ''हम इसके पक्ष में हैं कि रिश्ते सामान्य होने चाहिए। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पूर्व की स्थिति बहाल हो।'' उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि चीन से भूमि वापस लेने के लिए क्या किया जा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया, ''किसी ने एक बार विदेश नीति के मामले में इंदिरा गांधी जी से पूछा था कि वह बायीं ओर झुकाव रखती है या दायीं ओर? उन्होंने जवाब दिया कि वह भारतीय है और सीधी खड़ी हैं। बीजेपी और आरएसएस का एक अलग दर्शन है। जब उनसे दाएं या बाएं झुकाव के बारे में पूछा जाता है, तो वे कहते हैं कि वे आने वाले हर विदेशी के सामने सिर झुकाते हैं। यह उनकी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है।''

न्यू देहली पोस्ट
13 अप्रैल 2025
संपादकीय कार्यालय : मुद्रक व प्रकाशक आशीष कुमार द्वारा विभा पब्लिकेशन डी-160 बी, सेक्टर-7, नोएडा से मुद्रित एवं 262ए, सेक्टर-4, वैशाली गाजियाबाद से प्रकाशित। RNI NO. UPHIN/2013/49239
संपादक : आशीष कुमार, **प्रसार प्रबंधक** : दशरथ सिंह
Postal registration Number: UP/GBD-181/2013-15, **हमसे संपर्क करें** : postnewdelhi@gmail.com

संपादकीय

रात के अँधेरे से निकला ऐतिहासिक बिल

सरकार की महिमा ही है कि वह आधी रात को ही कई बड़े फैसले लेती है और जब देश की जनता सोती है तब वह संसद में कई विधेयक अजर बिलों को बहुमत के आधार पर पास कराती है। वक्फ संशोधन बिल देश के लिए इतिहास बने या नहीं बने लेकिन इस आधार पर तो यह ऐतिहासिक हो ही गया है कि इसे आधी रात को संसद में पास किया गया। आजाद भारत का यह भी एक अलग सच है। देश की आजादी भी आधे रात को ही मिली थी। लगता है पीएम मोदी उसी से सबक लेते हुए कई फैसले भी आधी रात को लेते रहे हैं। आधी रात के फैसले को खूब प्रचारित किया जाता है और इसका डंका भी बजाय जाता है। 2017 में भी सरकार ने कुछ इसी तरह का ऐतिहासिक फैसला आधी रात को ही लिया था। जुलाई महीने में आधी रात को जीएसटी का बिल मोदी सरकार ने संसद में पास कराया था। नोटबंदी का फैसला तो आधी रात को भले ही नहीं हुई थी लेकिन इसे फैसले को भी आठ बजे की रात्रि में ही मोदी जी ने लिया था।

वक्फ संशोधन बिल का पास कराने का फैसला भी दोनों सदनों में देर आधी रात के बाद ही लिया गया। इस खेल का अंजाम क्या होगा यह अभी किसी को पता नहीं है लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह एक असंवैधानिक फैसला है और संभव है कि कोर्ट में जाने के बाद इस फैसले को चुनौती भी दी जा सकती है। कांग्रेस ने तो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाने का ऐलान भी कर दिया है। जाहिर है यह मामला अब आगे तक चलेगा। बीजेपी कोर्ट में इस बिल को कैसे और कितना डिफेंड करेगी यह भी एक रोचक तथ्य हो सकते हैं।

केंद्र सरकार अजर बीजेपी से यह पूछा जा सकता है कि क्या वक्फ बिल की तरह ही देश की बड़ी कई बड़ी समस्याओं पर भी संसद में आधी रात तक बहस की जा सकती है। मोदी सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त पांच किलो राशन देते हैं। देश के इतनी बड़ी आबादी भी राशन लेने से चुकती नहीं। मोदी सरकार यह भी कहती है कि देश में अब गरीबी न के बराबर है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि भारत में भले ही कोई भूख से नहीं मरता हो लेकिन देश में गरीबी है इसे कोई इंकार नहीं कर सकता। क्या गरीबी के मसले पर ही संसद में आधी रात तक बहस की जा सकती है ? फिर बेरोजगारी ,महंगाई ,पडोसी देशों के साथ तनाव , महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध ,आर्थिक घपले और देश का भविष्य बेहतर हो इसको लेकर आधी रात तक संसद में बहस हो सकती है ? उत्तर तो यही होगा ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो प्रधानमंत्री आज तक देश की मीडिया के सामने नहीं आये वे भला संसद में क्या कुछ कहेंगे ? मणिपुर दो साल से जल रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की हालत ख़राब है। इस पर भी भी तो आधी रात तक चर्चा करके ऐतिहास बनाया जा सकता है। लेकिन यह सब शायद बीजेपी के अजेंडा में नहीं है।

तमिलनाडु पॉलिटिक्स

अन्नामलाई हटेंगे तभी होगा बीजेपी के साथ गठबंधन

राजनीतिक डेस्क

अगले साल तमिलनाडु में भी चुनाव होने हैं। बीजेपी कोशिश कर रही है कि अगले साल के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी सफलता मिल जाए। दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर जीत हो जाए और कुछ दलों के साथ मिलकर गठबंधन भी हो जाए ताकि तमिलनाडु की राजनीति में धमक बढ़ जाए। बीजेपी और भी बहुत कुछ चाह रही है। लेकिन कई दल ऐसे हैं जिन्हे बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई से चिढ़ है। कुछ दल चाहते हैं कि बीजेपी के साथ तभी गठबंधन हो सकता है जब अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाए। जाहिर है बीजेपी मुश्किल में फंसी हुई है। लेकिन अब उसकी मजबूरी भी है। अगर बीजेपी बिना गठबंधन किये चुनावी मैदान में जाती है तो उसे कुछ भी हासिल नहीं हो पायेगा और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी तो संभव है कि उसका खाता भी खुल जाए और कुछ सीटों पर जईरत भी हो जाए। ऐसे में अब माना जा रहा है कि तमिलनाडु के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई की विदाई होने वाली है। बताया जा रहा है कि वे भाजपा अध्यक्ष पद से हटाए जाएंगे क्योंकि उनकी वजह से अन्ना डीएमके से तालमेल की बात आगे नहीं बढ़ पा रही है।

यह अलग बात है कि लोकसभा का चुनाव हारने और लंदन में तीन महीने बीता कर लौटने के बाद अन्नामलाई ने अन्ना डीएमके के प्रति अपना रवैया बदल दिया था। लंदन से लौटने के बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि भाजपा तालमेल के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अन्ना डीएमके के सुप्रीमो ई पलानीसामी उनके रहते तालमेल के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों पलानीसामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उसमें दोनों पार्टियों के तालमेल के बारे में बातचीत हुई थी। परंतु दिल्ली से लौटने के बाद पलानीसामी थोड़े दिन चुप्पी साधे रहे और उसके बाद उनकी पार्टी की ओर से कहा गया कि अन्ना डीएमके तालमेल के लिए ओपन है। वह भाजपा, टीवीके या एनटीके से तालमेल कर सकती है। गौरतलब है कि टीवीके तमिल सुपरस्टार विजय की पार्टी है और पहले से दोनों पार्टियों के बीच तालमेल की बात चल रही है। इस बयान के बाद खबर आई कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को हटाएगी। कहा जा रहा है कि अन्नामलाई की राजनीति में ठोस आधार नहीं। उससे ज्यादा ड्रामे हैं। इसके बावजूद उनको हटाने का कारण यह बताया जा रहा है कि वे मजबूत पिछड़ी जाति गौंडर से आते हैं और ई पलानीसामी भी उसी समुदाय के हैं। अगर दोनों पार्टियों का गठबंधन होता है तो सर्वोच्च नेता का एक ही समुदाय से होना ठीक नहीं होगा।

क्या टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का संसद से निष्कासन गैर क़ानूनी था ?

राजनीतिक डेस्क

अंतर-संसदीय संघ यानी आईपीयू ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के 2023 में संसद से निष्कासन की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि वह इस आरोप से चिंतित है कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर जवाब मांगने के कारण मोइत्रा को बदले की कार्रवाई में निष्कासित कर दिया गया। आईपीयू ने 2023 में संसद से महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर चिंता और रोष ;प्रकट करते हुए कहा है कि, "बिना आम सहमति के अपनाई गई एक विवादास्पद रिपोर्ट के आधार पर और उन्हें उनसे संबंधित मामले में खुद को व्यक्त करने का अधिकार दिए बिना" संसद से निष्कासन कानून पर आधारित नहीं था। ''

बता दें कि दिसंबर 2023 में टीएमसी सांसद मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन 2024 में वे लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में वापस आ गईं। संसद में सवाल पूछने के लिए नकदी लेने के आरोपों के बाद उनका निष्कासन हुआ था । लोकसभा की आचार संहिता समिति ने उनके निष्कासन की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश की थी और स्पीकर ओम बिरला ने मोइत्रा को निचले सदन में अपना बचाव करने की अनुमति नहीं देते हुए उन्हें सदन सक्से निष्कासित कर दिया था। पूरा कदेश तब सन्न रह गया था। बीजेपी ठहाका लगाती रही।

आईपीयू ने सांसदों के मानवाधिकार समिति द्वारा अपने 176वें सत्र (जिनेवा, 3 से 19 फरवरी 2025) में अपनाए गए अपने फैसले में कहा है कि वह "शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से चिंतित है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि मोइत्रा के निष्कासन पर वोट एक विवादास्पद रिपोर्ट के आधार पर आम सहमति के बिना और उन्हें उनसे संबंधित मामले में खुद को व्यक्त करने का अधिकार दिए बिना हुआ, साथ ही आरोप है कि आचार संहिता समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद विजय सोनकर द्वारा उनके साथ भेदभावपूर्ण और पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार किया गया।" इस रिपोर्ट के आने के बाद आज देश के भीतर कोई चर्चा नहीं हो रही है अजर न ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और सोनकर से कोई सवाल पूछे जा रहे हैं। कोई भी यह भी नहीं पूछ रहा है कि आखिर ये सब क्यों किया गया ? सिर्फ इसलिए कि महुआ सरकार से सगवाल पूछ रही थी और सरकार को घेर रही थी ?

बता दें कि अंतर -संसदीय संघ यानी आईपीयू राष्ट्रीय संसदों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है. इसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही विधायिकाओं के बीच लैंगिक समानता को आगे बढ़ाना, राजनीति में युवाओं की भागीदारी को सशक्त बनाना और सतत विकास शामिल हैं ।

इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1889 में अंतर-संसदीय सम्मेलन के रूप में की गई थी । इसके संस्थापक फ्रांस के राजनेता फ्रेडरिक पैसी और यूनाइटेड किंगडम के विलियम रैंडल क्रेमर थे , जिन्होंने राजनीतिक बहुपक्षीय वार्ता के लिए पहला स्थायी मंच बनाने की मांग की थी। प्रारंभ में आईपीयू की सदस्यता व्यक्तिगत सांसदों के लिए आरक्षित थी , लेकिन बाद में इसे संप्रभु राज्यों की विधानसभाओं को शामिल करने के लिए बदल दिया गया। 2020 तक, 180 देशों की राष्ट्रीय संसदें आई[आईपीयू की सदस्य हैं, जबकि 13 क्षेत्रीय संसदीय विधानसभाएँ सहयोगी सदस्य हैं।

आईपीयू अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थानों के विकास की सुविधा प्रदान करता है। जिसमें स्थायी मध्यस्थता न्यायालय , राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र शामिल हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मंचों को प्रायोजित करता है और उनमें भाग लेता है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा रखता है । नतीजतन इस संगठन से जुड़े आठ व्यक्ति नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं ।

संगठन का प्रारंभिक उद्देश्य विवादों का मध्यस्थता करना था। आईपीयू ने हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । समय के साथ, इसका मिशन लोकतंत्र और अंतर-संसदीय संवाद को बढ़ावा देने की दिशा में विकसित हुआ है।आईपीयू ने अंतर-सरकारी स्तर पर संस्थाओं की स्थापना के लिए काम किया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र भी शामिल है।

महुआ मोइत्रा मामले में आईपीयू ने कहा कि वह "विशेष रूप से उन रिपोर्टों से चिंतित है कि मोइत्रा को कानून या लागू संसदीय नियमों के किसी भी उल्लंघन की अनुपस्थिति में दंडित किया गया था; नल्ला पोएना सिने लेगे के कानूनी सिद्धांत की सार्वभौमिक और अनुल्लंघनीय प्रकृति को याद करता है , जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऐसे कार्य या चूक के कारण किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो उस समय अपराध नहीं था जब वह किया गया था। और इसके पास उपलब्ध जानकारी के प्रकाश में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने का निर्णय कानून पर आधारित नहीं था।"

गौरतलब है कि पहले बताया था कि सोनकर की अध्यक्षता वाली समिति की आलोचना उसकी बैठकों के तरीके के कारण की गई है। ऐसी ही एक बैठक में मोइत्रा ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों के पांच सदस्य भी वॉकआउट कर गए थे। एक विपक्षी सांसद ने द वायर से कहा था, "उनसे पूछा गया था कि अपनी यात्राओं के दौरान वह दुबई के किस होटल में रुकी थीं और किसके साथ रुकी थीं, आदि।विपक्षी सदस्यों ने एक आधिकारिक मंच पर एक महिला सांसद से पूछे गए इन सवालों को बहुत आपत्तिजनक पाया और बैठक से बाहर चले गए। " द वायर ने यह भी बताया था कि आचार समिति की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए सांसदों को केवल दो घंटे का समय दिया गया था, तथा रिपोर्ट पेश होने के बाद 30 मिनट की चर्चा निर्धारित की गई थी, लेकिन बहस शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर मोइत्रा के निष्कासन की घोषणा कर दी गई और आवंटित छोटे से समय का भी पूरा उपयोग नहीं किया गया। आईपीयू ने कहा है कि मोइत्रा को निष्कासित करना और संसद में उनकी सीट छीनना "एक अत्यंत गंभीर सजा" थी।

आईपीयू ने अपने फैसले में कहा कि वह इस आरोप से चिंतित है कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर जवाब मांगने के लिए मोइत्रा को बदले की कार्रवाई में निष्कासित किया गया। मोइत्रा ने निष्कासन के बाद आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार और अडानी समूह के बीच कथित सांठगांठ पर सवाल उठाने की उनकी हिम्मत के कारण समिति उनके खिलाफ पक्षपाती थी।

आईपीयू ने कहा कि वह इस मामले की जांच जारी रखेगा, साथ ही उसने लोकसभा महासचिव से अनुरोध किया कि वह इस निर्णय से लोकसभा अध्यक्ष को अवगत करा दें। उसने यह भी कहा कि चूंकि उसे संसदीय नियमों में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, इसलिए उसने संसद से "इस अवसर का उपयोग अपनी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए करने का आह्वान किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मोइत्रा के निष्कासन को जन्म देने वाली स्थिति फिर से न हो और संसद के सभी सदस्यों, बहुमत और विपक्ष दोनों के अधिकारों को कानून और व्यवहार में समान रूप से संरक्षित किया जाए"।

669 एशियाई शेरों की मौत, कौन जिम्मेदार?

न्यूज़ डेस्क

जीवन और मौत तो प्रकृति के हाथ में है लेकिन प्रकृति के संरक्षक और पहरेदार ही जब प्रकृति के साथ खेलना शुरू कर दे तो उसका अंजाम क्या होता है यह हमारे संरक्षित वन्य जीवो की हो रही मौत से पता चलता है। अभी संसद में सरकार की तरफ से एक आंकड़ा पेश किया गया है जिसमे बताया गया है कि पिछले पांच सालों में 669 एशियाई शेरो की मौत हो गई है। बड़ी बात तो यह है कि देश में गुजरात का गिर जंगल ही एक मात्र शेरों के लिए प्राकृतिक आवास है लेकिन गुजरात सरकार के जो आंकड़े बताते हैं वे चौंकाने वाले हैं। संसद में जो आंकड़े दर्ज किये गए हैं वे गुजरात सरकार इकट्ठा किये गए आंकड़े ही है।

राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि 2020 में 142 शेर, 2021 में 124, 2022 में 117, 2023 में 121 और 2024 में 165 शेरों की मौत हुई। रिपोर्ट के अनुसार, शेरों की मौत के कथित मामलों में बुढ़ापा, बीमारी, लड़ाई में चोट लगना, शावकों की मृत्यु, खुले कुओं में गिरना, बिजली का झटका, दुर्घटनाएं शामिल हैं। लेकिन सरकार के ये आंकड़े ही सही हैं ?क्या शेरोके शिकार नहीं हो रहे हैं ? क्या शेर जहाँ रहते हैं उन इलाकों का भरपूर संरक्षण किया जाता है ? क्या क्या अवैध शिकार करने वालों से हमारे देश के वन जीव सुरक्षित हैं ? ऐसे बहुत से सवाल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022 तक भारत में बाघों की संख्या 3,682 थी । - जो दुनियाभर के वाइल्ड टाइगर्स की आबादी का लगभग 75 प्रतिशत है।

बता दें कि भारत ने बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। शुरुआत में इसमें 18,278 वर्ग किलोमीटर में फैले नौ बाघ अभयारण्य शामिल थे। वर्तमान में भारत में 55 बाघ अभयारण्य हैं जो बाघों के आवास के 78,735 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं। महाराष्ट्र में भी पिछले 15 वर्षों में बाघों की आबादी में नाटकीय वृद्धि 2024 444 हो गई थी। पहले यह दसंख्या 150 की थी। लेकिन इसी समय 2 से 19 जनवरी के बीच, थोड़े से अंतराल में आठ बाघों के मृत पाए जाने की खबर संरक्षण समुदाय के लिए एक झटका थी। इनमें दो नर शावक, एक मादा शावक और बाकी वयस्क बाघ शामिल हैं। इनमें से कम से कम दो मौतें स्पष्ट रूप से संदिग्ध हैं।

2 जनवरी को चंद्रपुर ब्रम्हपुरी सिंदेवाही वन क्षेत्र में एक नर बाघ मृत पाया गया; वन विभाग ने कहा कि बाघ की मृत्यु वृद्धावस्था के कारण हुई। लेकिन 6 जनवरी को भंडारा जिले के तुमसर वन क्षेत्र में एक मृत बाघ मिला, जिसका शरीर चार टुकड़ों में कटा हुआ था। जांच में पता चला कि बाघ द्वारा मवेशियों का शिकार करने के बाद ग्रामीणों ने प्रतिशोध में उसे मार डाला था। यवतमाल जिले के पंढरकवड़ा वन क्षेत्र में एक कोयला खदान में एक और बाघ मृत पाया गया; उसके दो कैनाइन और 12 पंजे गायब थे, जिससे संदेह पैदा हुआ कि यह अवैध शिकार का मामला था । फिर इसी साल 8 जनवरी को पेंच टाइगर रिजर्व के देवलापार वन रेंज में एक शावक मृत पाया गया, जिसे वन अधिकारियों ने प्राकृतिक कारणों से मृत घोषित कर दिया। पांचवीं मौत 9 जनवरी को ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में एक बाघिन की हुई थी; चूंकि उसका शरीर सुरक्षित था, इसलिए वन अधिकारियों का मानना है कि यह मौत आपसी लड़ाई का नतीजा हो सकती है।

नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 12 सालों के दौरान कुल 1386 बाघों की मौत हुई, जिसमें 50 प्रतिशत मौत टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हुई। 42 प्रतिशत बाघों की मौत टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बाहर हुई और 8 प्रतिशत बाघों पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ मरे हैं।: पिछले 12 सालों के दौरान देश भर में सबसे ज्यादा बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई।

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में देशभर के मुकाबले बाघों की अच्छी संख्या है। कॉर्बेट व आसपास के इलाकों में भी बाघों की अच्छी मौजूदगी मिल जाती है। हालांकि, इसके बीच यहां हर साल बाघ अपनी जान भी गंवा रहे हैं. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मुताबिक, उत्तराखंड में पिछले 12 सालों के दौरान हर साल औसतन 11 बाघों ने अपनी जान गंवाई हैं। वहीं, पिछले साल 2024 की बात करें तो उत्तराखंड में 8 टाइगर्स की मौतें दर्ज हुई हैं। वैसे बीते सालों की तुलना में साल 2024 में मौत का ये आंकड़ा कम हुआ है, लेकिन इस स्थिति को संतोषजनक बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। खासतौर से राष्ट्रीय स्तर पर बाघों की मौत के आंकड़े सालाना 100 से पार ही रिकॉर्ड हो रहे हैं।

देश में में 50 प्रतिशत बाघों की मौत टाइगर रिजर्व क्षेत्र के भीतर ही हो रही है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 12 सालों के दौरान कुल 1386 बाघों की मौत हुई, जिसमें 50 प्रतिशत मौत टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हुई। 42 प्रतिशत बाघों की मौत टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बाहर हुई और 8 प्रतिशत बाघों पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ मरे हैं।: पिछले 12 सालों के दौरान देश भर में सबसे ज्यादा बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई, यहां 355 बाघों को जान गंवानी पड़ी. दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 261 तो तीसरे नंबर पर कर्नाटक में 179 टाइगर्स की मौत हुई। उत्तराखंड चौथे नंबर है, यहां 12 सालों में 132 टाइगर्स ने जान गंवाई।

गडकरी ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना

राजनीतिक डेस्क

पिछले दिनों नागपुर संघ कार्यालय में पीएम मोदी की संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात हुई। इस मुलाकात की खूब चर्चा भी हुई। नागपुर संघ कार्यालय से एक तस्वीर सामने आयी जिसमे एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ,मोहन भागवत ,नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिख रहे थे। खबर के मुताबिक़ मोदी ने नागपुर के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कई जगह भाषण भी दिए। संघ कार्यालय में भी उन्होंने कई बातें कही लेकिन गडकरी को नहीं बोलने दिया गया। गडकरी उसी नागपुर से सांसद हैं और मोदी सरकार के सबसे अव्वल मंत्री भी हैं। उनके काम की प्रशंसा विपक्षी भी करते हैं।

लेकिन गडकरी की यही पहचान नहीं है। उनकी पहचान बेबाक नेताओं की रही है। वे सब कुछ बोलते हैं और कटाक्ष भी खूब करते हैं। बोलने से चूकते नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ठाणे में एक कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक नेताओं के बढ़ते दिखावे की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जब मेरे पास मंत्री पद नहीं था तो कुत्ता भी मेरे स्वागत के लिए नहीं आता था। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि जब मंत्री पद नहीं रहेगा तब भी मेरे स्वागत में लोग शायद ही आएंगे। उनका यह बयान नागपुर में हुए पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद आया है, जहां गडकरी को बोलने का मौका भी नहीं दिया गया था।

राजनीतिक हलकों में चर्चाएं होती रहती हैं कि

उनके इसी अंदाज को देखते हुए खुद पीएम मोदी भी घबराते हैं। यही वजह थी कि नागपुर के एक कार्यक्रम में गडकरी को बोलने का मौका नहीं दिया गया।लेकिन जब ठाणे में एक कार्यक्रम में गडकरी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने दिखावे की राजनीति पर जमकर हमला बोला।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर हैं। उनकी बातों का असर दूर तक होता है। उन्होंने नेताओं के स्वागत में लगाए जाने वाले बैनर-पोस्टरों पर निशाना साधा है। ठाणे के एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी पोस्टर लगवाने पर एक रुपया भी खर्च नहीं किया और न ही कभी करूंगा। हाल ही में नागपुर में पीएम मोदी के लिए ढेर सारे स्वागत के पोस्टर लगे थे। माना जा रहा है कि गडकरी का इशारा उधर ही था।

कार्यक्रम में आगे बोलते हुए गडकरी ने कहा कि मेरे स्वागत के लिए कोई कुत्ता भी नहीं आता था, लेकिन अब 'जेड प्लस सुरक्षा' होने के कारण कुत्ता आने लगा है। आजकल छोटे-छोटे राजनीतिक पद मिलने पर लोग खुद को 'साहब' समझने लगते हैं और होर्डिंग लगाते हैं। बड़े की तो बात ही छोड़िए। सूत्रों की मानें तो उनका यह इशारा पीएम मोदी के आगमन पर नागपुर में लगे जमकर पोस्टर पर था। गडकरी ने आगे कहा कि आज के दौर में किसी को अस्थायी राजनीतिक पद भी मिल जाए तो वे खुद को बड़ा साहब समझने लगते हैं।

ठाणे के डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह में एक सत्कार समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोडकर और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। इस दौरान गडकरी ने अपने एक अनुभव को साझा करते हुए कहा कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा उनसे मिलने आने वाले थे, लेकिन उन्हें उनके निवास का पता नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने गडकरी से संपर्क किया। जब गडकरी ने टाटा से उनके ड्राइवर को फोन देने के लिए कहा, तो रतन टाटा ने जवाब दिया कि वे खुद गाड़ी चला रहे हैं।

यूपी के बुलडोजर राज से सुप्रीम कोर्ट नाराज

न्यूज़ डेस्क

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के सामाजिक ,आर्थिक उत्थान के लिए भले ही कई काम किये हों लेकिन उनकी सबसे ज्यादा चर्चा बुलडोजर को लेकर ही होती है। देश के वे पहले मुख्यमंत्री हैं जो बुलडोजर की बात करते रहे हैं और एक्शन करने में भी कोताही नहीं करते। योगी राज के बुलडोजर नीति से भले ही भक्त समाज को ख़ुशी मिलती हो लेकिन देश की शीर्ष अदालत इससे काफी नाराज हैं और दुखी भी। ऐसे ही प्रयागराज में जब बुलडोजर का एक्शन हुआ तो शीर्ष अदालत विफर पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की खिंचाई की। कोर्ट ने शहर में मकान ढहाने को अमानवीय और अवैध बताया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमानवीय तरीके से की गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में कानून का शासन है और नागरिकों के आवासीय ढांचों को इस तरह से नहीं ढहाया जा सकता। पीठ ने कहा, 'इसने हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। आश्रय का अधिकार, कानून की उचित प्रक्रिया जैसी कोई चीज होती है।'

इसके बाद शीर्ष अदालत ने प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह छह हफ्ते के अंदर मकान मालिकों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दे। इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने प्रयागराज में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई की थी और कहा था कि इससे चौंकाने वाला और गलत संकेत गया है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा था कि राज्य सरकार ने गलत तरीके से मकानों को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह जमीन गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद की है। वह 2023 में मारा गया था। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनके मकान ध्वस्त कर दिए गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं को कथित तौर पर प्रयागराज जिले के लूकरगंज में कुछ निर्माणों के संबंध में 6 मार्च, 2021 को नोटिस दिया गया था।

बीजेपी के शरण में पहुंचे सपा के तीन विधायक

न्यूज़ डेस्क

उत्तरप्रदेश में विधान सभा चुनाव तो 2027 में होने हैं लेकिन बीजेपी की तैयारी अभी से ही शुरू है ताकि सूबे में फिर से बीजेपी की सरकार बनाई जाए और समाजवादी पार्टी को धूल चटाई जाए। बीजेपी की नजर अब सपा के उन विधायकों पर जा टिकी है जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक़ बीजेपी सपा के कई नेताओं को टटोल रही है। ऐसे नेता की खोज की जा रही है जिनका अपने इलाके में जनाधार है। इसी कड़ी में पिछले दिन सपा के तीन विधायक गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुँच गए। ये तीनो सपा के बागी विधायक हैं जिन्होंने राज्य सभा चुनाव के दौरान सपा से बगावत कर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट डाले थे। ये तीन विधायक हैं अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक अभय सिंह , राकेश सिंह और विनोद चतुर्वेदी। इन तीनो ने शाह से मंगलवार को मुलाकात की है। माना जा रहा है ये तीनो अब बीजेपी के साथ जायेंगे। इस दौरान भाजपा के राज्यसभा सांसद संजय सेठ भी मौजूद रहे। दरअसल फरवरी 2024 मे हुए राज्यसभा चुनाव में इन लोगो ने भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ को वोट किया था।

माना जा रहा है की औपचारिक तौर पर ये तीनों विधायक बीजेपी मे शामिल होंगे। योगी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले गृहमंत्री अमित शाह से हुई इन बागी विधायकों की मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। अभय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अमित शाह से आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। कहा जा रहा है कि सपा से बगावत करने के बाद से ही ये विधायक भविष्य की राजनीति को लेकर चिंतित हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन विधायकों ने भाजपा का समर्थन किया था। हालांकि, विधायकों के भगवा ब्रिगेड में आने के बाद भी भाजपा को लोकसभा चुनाव में फायदा नहीं हुआ था। इस मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'जो अपने दर से दगा करता है, वो दर-दर भटकता है।' माना जा रहा है कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा होने के बाद जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। जिसके चलते बागी विधायकों की गृह मंत्री के साथ मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। तीनों विधायकों ने गृह मंत्री शाह से मुलाकात करके अपनी राजनीतिक सुरक्षा से जुड़ी परेशानियों के बारे में उन्हें अवगत कराया है।

आखिर रांची में सीएम हेमंत सोरेन से क्यों मिले गौतम अडानी ?

न्यूज़ डेस्क

झारखंड की राजनीति उस समय अचानक गर्म हो गई जब उद्योगपति गौतम अडानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुँच गए। दोनों की मुलाकात सीएमओ की बजाय सीएम के आवास पर हुई। बहुत कुछ बातें हुई लेकिन बातों का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। उधर जैसे ही इस मुलाकात की जानकारी विपक्षी बीजेपी को लगी ,सूबे की राजनीति गरमा गई। हमले होने लगे। क्या बात हुई है उसका खुलासा करने की मांग की गई। इसके साथ ही सीएम हेमंत पर और भी कई आरोप बीजेपी ने मढ़ दिया । बीजेपी ने कहा कि अभी तक कांग्रेस और झामुमो अडानी के खिलाफ बोलते रहे हैं फिर बंद कमरे में क्या बात होने लगी ? उधर कांग्रेस और झामुमो ने कहा है कि "व्यापारियों का सीएम से मिलना स्वाभाविक है, बैठक को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की जरूरत नहीं है। ''

जानकारी के मुताबिक़ बीते शनिवार को करीब दो घंटे तक अडानी और हेमंत के बीच बैठक हुई। यह बैठक बंद कमरे में हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़ "बैठक में चर्चा गोड्डा परियोजना, राज्य के सबसे बड़े अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट और हजारीबाग जिले के गोंदलपुरा कोयला ब्लॉक के इर्द-गिर्द केंद्रित थी, जिसे 2020 में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी को नीलाम कर दिया गया था।" बता दें कि अडानी-सोरेन की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब झारखंड के मुख्यमंत्री 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाया खनन बकाये को लेकर केंद्र के साथ विवाद में हैं। इस मुलाकात से यह चर्चा तेज हो गई है कि सीएम सोरेन केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक निवेश की तलाश के लिए कोई विकल्प तलाश रहे हैं। पिछले साल के लोकसभा चुनाव

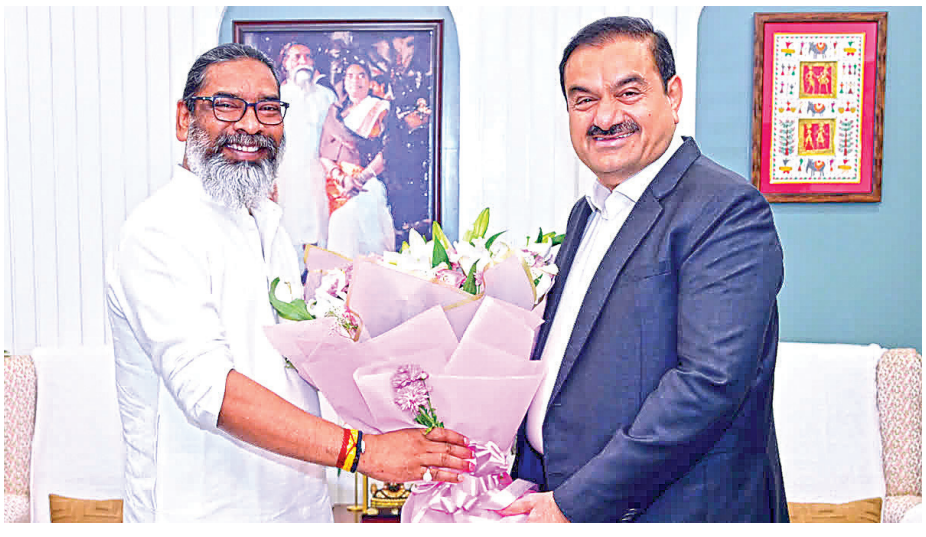

मरांडी ने कहा, "अब उन लोगों पर सवाल उठना चाहिए जिन्होंने अतीत में चौक-चौराहों से लेकर सदन तक झूठा दावा किया था कि भाजपा अडानी के साथ घुलमिल गई है। मुख्यमंत्री ने उनसे (उनके घर के बजाय) कार्यालय में मुलाकात क्यों नहीं की और उनके बीच क्या निजी चर्चा हुई? क्या यह पाखंड नहीं है?

और उसके बाद के विधानसभा चुनावों से पहले विपक्षी दल भारत के दोनों गुटों- जेएमएम और कांग्रेस ने बार-बार भाजपा पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि वह अडानी जैसे उद्योगपतियों के साथ नजदीकी बढ़ा रही है। राहुल गांधी शुरू से ही अडानी के खिलाफ रहे हैं और आज भी हैं।

अपनी बात पर जोर देने और उद्योगपति से अपनी दूरी दिखाने के लिए पिछले साल नवंबर में तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अडानी से प्रस्तावित यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपये का दान लेने से इनकार कर दिया था। पिछले आरोपों की ओर इशारा करते हुए झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस से अपनी चुप्पी तोड़ने और अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।

मरांडी ने कहा, "अब उन लोगों पर सवाल उठना चाहिए जिन्होंने अतीत में चौक-चौराहों से लेकर सदन तक झूठा दावा किया था कि भाजपा अडानी के साथ घुलमिल गई है। मुख्यमंत्री ने उनसे (उनके घर के बजाय) कार्यालय में मुलाकात क्यों नहीं की और उनके बीच क्या निजी चर्चा हुई? क्या यह पाखंड नहीं है? एक तरफ वे उनकी (अडानी की) आलोचना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करते हैं... ऐसी निजी मुलाकातें केवल यही संकेत देती हैं कि कुछ गड़बड़ है।" वर्तमान में, गोड्डा परियोजना प्रतिदिन 1,600 मेगावाट बिजली पैदा करती है, जिसे पड़ोसी बांग्लादेश को आपूर्ति की जाती है, जबकि गोंडलपुरा में खनन परियोजना को ग्रामीणों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे 500 एकड़ भूमि के अधिग्रहण में देरी हो रही है।

मरांडी ने यह भी बताया कि सत्तारूढ़ विधायकों - कांग्रेस के प्रदीप यादव और जेएमएम के स्टीफन मरांडी ने हाल ही में गोड्डा में भूमि अधिग्रहण पर चिंता जताई थी, आरोप लगाया था कि इस प्रक्रिया में पुनर्वास अधिनियम, 2013 और संथाल परगना काश्तकारी (एसपीटी) अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। सोरेन सरकार ने बाद में परियोजना के लिए अडानी समूह को हस्तांतरित भूमि की वैधता की समीक्षा करने के लिए मुख्य सचिव अलका तिवारी के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया।

अब मरांडी के आरोपों को खारिज करते हुए जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा कि इस तरह की "नियमित बातचीत को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए"। उन्होंने कहा, "सोरेन सरकार लोगों के हितों के प्रति सजग है, जो चुनावों में स्पष्ट था। हमारी सरकार लोगों के पलायन को रोकने और रोजगार पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नए संयंत्रों की स्थापना सहित कोई भी औद्योगिक विकास अंततः राज्य और उसके लोगों को लाभान्वित करेगा।" कांग्रेस ने अपने सहयोगी का मजबूती से समर्थन किया, एआईसीसी झारखंड प्रभारी के राजू ने कहा कि यादव केवल लोगों के मुद्दे उठा रहे थे। उन्होंने कहा, "इसके अलावा, व्यापारियों का कई राज्यों का दौरा करना सामान्य बात है।"

क्या बीजेपी अध्यक्ष की रेस में आगे चल रही हैं निर्मला सीतारमण ?

राजनीतिक डेस्क

बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर सस्पेंश कायम है। इसके साथ ही यह भी सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा। फिलहाल संसद का बजट सत्र चल रहा है, जो की 4 अप्रैल तक चलना है। इसलिए इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा पार्टी की ओर से की जाएगी, इसकी संभावना कम है।

यह बात और है कि बीजेपी के अगले अध्यक्ष को लेकर संघ और बीजेपी के बीच पसंद और नापसंद को लेकर बात उलझी हुई है लेकिन यह भी तय है कि संघ और बीजेपी के बीच बात उलझी तो पार्टी को इस बार पहली महिला अध्यक्ष भी मिल सकती है। निर्मला सीतारमण पार्टी की नयी अध्यक्ष बन सकती है।

वैसे बीजेपी के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कुछ अन्य नाम हैं, जो सबसे आगे चल रहे हैं। इन नामों में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान और शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। इन सब के अलावा एक अन्य नाम है, जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है. उस चेहरे का नाम भूपेंद्र यादव है। भूपेंद्र यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी भी माना जाता है। वैसे कुछ लोगों की तरफ से योगी आदित्यनाथ के नाम को भी उछला जा रहा है लेकिन इसकी सम्भावना कम ही दिखती है। योगी आदित्यनाथ अभी सीएम के पद से हटने को तैयार नहीं है लेकिन अगर पार्टी कोई निर्णय लेती है तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी मुहर लग सकती है। योगी अभी संघ के ख़ास माने जाते हैं। संघ को लग रहा है कि जो काम अभी तक मोदी नहीं कर पाए उस काम को योगी अंजाम दे सकते हैं।

लेकिन सूत्रों की बात माने तो बीजेपी के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम सबसे आगे चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीतारमण साउथ से आती हैं। तमिलनाडु में इस समय परिसीमन का मामला गरमाया हुआ है। विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। उनका तर्क है कि अगर परिसीमन होता है, तो दक्षिण भारत में सीटें घट जाएंगी और उत्तर भारत में सीटें बढ़ जाएंगी। जिससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा।

दक्षिण भारत में बीजेपी की सरकार नहीं है। कर्नाटक की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। बीजेपी की कोशिश है कि परिसीमन विवाद खत्म हो जाए और आगामी चुनावों में बीजेपी को फायदा मिले। अगर इन बातों पर गौर किया जाए, तो निर्मला सीतारमण का नाम बीजेपी के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे दिखता है। यह भी बता दें कि अध्यक्ष को लेकर ही पिछले दिनों पीएम मोदी और संघ प्रमुख भागवत की मुलाकात संघ कार्यालय नागपुर में हुई। कोई 25 साल बाद कोई प्रधानमंत्री संघ दफ्तर पहुंचे थे। संघ और मोदी के बीच किन मुद्दों पर बात हुई इसकी जानकारी तो अभी सामने नहीं है लेकिन मन जा रहा है कि अध्यक्ष को लेकर संघ की समझ कुछ और ही है। संघ इस बार अपनी पसंद का कोई अध्यक्ष चाह रहा है।

इधर जेपी नड्डा फिलहाल एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 2023 में ही खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया था। नड्डा इस समय केंद्रीय मंत्री और पार्टी अध्यक्ष पद दोनों को संभाल रहे हैं। लेकिन यह पार्टी के 'एक व्यक्ति एक पद' के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए बीजेपी की ओर से बहुत जल्द नये अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर सस्पेंश कायम है। इसके साथ ही यह भी सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा। फिलहाल संसद का बजट सत्र चल रहा है, जो की 4 अप्रैल तक चलना है। इसलिए इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा पार्टी की ओर से की जाएगी, इसकी संभावना कम है। 18 से 20 अप्रैल के बीच बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक बेंगलुरु में होनी है। ऐसी संभावना है कि इसी बीच बीजेपी नये राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है।

दिल्ली दंगा : बीजेपी नेता और मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज होगा एफआईआर

न्यूज़ डेस्क

बीजेपी नेता और दिल्ली के कानून और न्याय मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ दिल्ली दंगा के मामले में अब एफआईआर दर्ज होगा। उनपर क़ानूनी कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली के कानून एवं न्याय मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ शहर के उत्तरपूर्वी हिस्से में 2020 में हुए दंगों में उनकी कथित भूमिका को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने और आगे की जांच करने का निर्देश दिया है । ऐसे में अब कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने शिकायतकर्ता यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास की अर्जी मंजूर कर ली, जिन्होंने मिश्रा के साथ-साथ दयालपुर थाने के तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) और भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पार्टी के पूर्व विधायक जगदीश प्रधान सहित पांच अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।

याचिका मंजूर करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि मिश्रा के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनता है। 2020 में 24 से 26 फरवरी के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसमें 53 लोग मारे गए थे, 500 से अधिक घायल हुए थे और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। इस साल फरवरी में, दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि मिश्रा को इस मामले में "फंसाया" जा रहा है और 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने अदालत को बताया था कि दंगों के पीछे की बड़ी साजिश में मिश्रा की भूमिका की पहले ही जांच की जा चुकी है और उनके खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है। उधर महमूद प्राचा द्वारा अदालत में पेश किए गए इलियास ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसने मिश्रा और अन्य लोगों को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कर्दमपुरी में एक सड़क को अवरुद्ध करते और विक्रेताओं की गाड़ियों को नष्ट करते देखा था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि तत्कालीन पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), उत्तर-पूर्वी दिल्ली, अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिश्रा के बगल में खड़े थे और प्रदर्शनकारियों को क्षेत्र खाली करने या परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे थे।

शिकायतकर्ता ने यह भी कहा था कि उसने तत्कालीन दयालपुर एसएचओ को भाजपा नेताओं प्रधान और बिष्ट के साथ उत्तर-पूर्वी दिल्ली में मस्जिदों में तोड़फोड़ करते देखा था।मार्च में, एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा कि वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दर्ज एक अन्य मामले के संबंध में मिश्रा के खिलाफ आरोपों पर दलीलें सुनना शुरू करेगी, जिसमें उन पर फरवरी में हुए 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान सांप्रदायिक दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था।

ओडिशा में कांग्रेस बीजद की जगह लेने की कर रही तैयारी

राजनीतिक डेस्क

ओडिशा में कांग्रेस बड़ा दाव खेलने जा रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि जिस तरह से नवीन पटनायक राजनीति से थक गए हैं और बुढ़ापे का शिकार होकर पार्टी को समय नहीं दे रहे हैं ऐसे वक्त मेर अगर कांग्रेस को मजबूत कर दिया जाए तो आगामी राजनीति उसके पक्ष में हो सकती है। कांग्रेस को यह भी लग रहा है कि बीजद अब कमजोर होती जा रही है और संभव है कि उसके अधिकतर नेता पाला बदल सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को चुनौती देने के लिए अब कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है।

राजनीति में कब क्या हो जाए यह कौन जाने ! वक्त और हालात के साथ राजनीति बदल जाती है अजर नेताओं के सुर भी बदल जाते हैं। यह वक्त का ही खेल है कि बीजद मुखिया नवीन पटनायक लम्बे समय तक सत्ता का लाभ लेते रहे। बीजद की राजनीति जब उफान पर थी तब कांग्रेस रसातल में चली गई लेकिन इसी बीच बीजेपी ने वहां अपनी जमीन तैयार कर ली। पहले बीजेपी ने बीजद के साथ गठबंधन किया। सरकार भी चलाई और जब उसे लगा कि अब पाला बदलने का समय आ गया है तो उसने वही किया जो अब तक करती रही है। गठबंधन के समय नवीन पटनायक बीजेपी की नजर में सबसे बढ़िया नेता थे लेकिन अब वही नवीन पटनायक बीजेपी की नजर में खलनायक बने हुए हैं। यह समय का ही तो खेल है। नवीन पटनायक कहने को तो समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। वे जनता परिवार के हिस्सा रहे हैं लेकिन सत्ता की कुर्सी ने नवीन पटनायक को भी अंधा कर दिया था। बार -बार विपक्षी दलों की आस तरहटी थी कि संसद में उसे नवीन पटनायक का साथ मिलेगा लेकिन वे बीजेपी का ही साथ देते रहे। दर्जनों बिलों का समर्थन करते रहे। लेकिन अब वही नवीन पटनायक बदल से गए हैं। मौन भी हैं और बीजेपी के खेल को समझ भी रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी ओडिशा में बड़ी राजनीति कर रही है। राहुल गांधी ने अपने चहेते नेता भक्त चरण दास को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वे दलित समुदाय से आते हैं और कुछ समय पहले बिहार के प्रभारी थी। राहुल ने ओडिशा उनके हवाले करके सारे संसाधन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि ओडिशा में वापसी का समय आ गया है। चूंकि 24 साल तक शासन में रहने के बाद बीजू जनता दल हार कर सत्ता से बाहर हुई है और उसके नेता नवीन पटनायक की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। चुनाव में उनकी सेहत का मामला भी उठा था। तभी कांग्रेस नेता मान रहे हैं कि 2029 के चुनाव में वे बीजद को बहुत मजबूत नेतृत्व देने की स्थिति में शायद नहीं रहें।

> कांग्रेस पार्टी ओडिशा में बड़ी राजनीति कर रही है। राहुल गांधी ने अपने चहेते नेता भक्त चरण दास को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वे दलित समुदाय से आते हैं और कुछ समय पहले बिहार के प्रभारी थी। राहुल ने ओडिशा उनके हवाले करके सारे संसाधन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि ओडिशा में वापसी का समय आ गया है।

तभी कांग्रेस ओडिशा में भाजपा से सीधा मुकाबला बनाने के लिए रात दिन एक किए हुए है। विधानसभा में मुख्य विपक्षी बीजद है लेकिन कांग्रेस के 14 विधायक उससे ज्यादा सक्रिय दिखते हैं। पिछले दिनों हंगामे की वजह से कांग्रेस के 12 विधायकों को निलंबित किया गया। पार्टी महिलाओं का मुद्दा लेकर सड़क पर उतरी है। एक सामूहिक बलात्कार की घटना के खिलाफ पार्टी प्रदर्शन कर रही है। यह याद भी दिलाया जा रहा है कि 1999 में गैंगरेप की एक घटना के बाद ही कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना था और वह सत्ता से बाहर हुई थी। कांग्रेस की महिला विधायक सोफिया फिरदौस को महिलाओं के खिलाफ अपराधों को मुद्दा उठाने के लिए आगे किया गया है। कांग्रेस राज्य में बीजद की जगह लेना चाहती है।

प्रकाश करात ने क्यों कहा तीन सवालों के जवाब हैं मोदी और बीजेपी

राजनीतिक डेस्क

सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी की प्रकृति का अंदाजा तीन सवाल पूछकर लगाया जा सकता है - कौन डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त होने का दावा करता है? गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का करीबी दोस्त कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति कौन वफादार है? 'इन तीनों सवालों के जवाब एक ही हैं -- नरेन्द्र मोदी और बीजेपी। ये शब्द हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतरिम समन्वयक प्रकाश करात के। वे पिछले दिनों मदुरै में पार्टी की 24 वीं कांग्रेस को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केवल वामपंथियों के पास ही हिंदुत्व के ''नव-फासीवाद'' से लड़ने और उसका मुकाबला करने की क्षमता है।करात ने यह भी कहा कि सीपीआई (एम) बीजेपी के सामने एक वामपंथी और लोकतांत्रिक विकल्प बनाने की दिशा में काम करेगी।और पार्टी कांग्रेस की यह बैठक आगामी दिनों में सीपीआई (एम) की कार्यशैली की दिशा तय करेगी। करात ने दावा किया कि मोदी सरकार ''हिंदुत्व-कॉरपोरेट गठजोड़ का प्रतिनिधित्व करती है, जो अमेरिकी साम्राज्यवाद से निकटता से जुड़ा हुआ है''। उन्होंने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में सरकार ''नव-फासीवादी विशेषताओं'' को प्रदर्शित कर रही है, जिसमें मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाना शामिल है।

करात ने कहा, ''यह वामपंथ ही है जिसके पास हिंदुत्व नव-फासीवाद से लड़ने और उसका मुकाबला करने के लिए वैचारिक क्षमता और दृढ़ विश्वास है। केवल वामपंथी ही हमारे देश में साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर सकते हैं। वामपंथी लोकतांत्रिक विकल्प बनाने के लिए माकपा सभी वामपंथी ताकतों के साथ मिलकर काम करेगी।वरिष्ठ वामपंथी नेता ने यह भी कहा कि पार्टी कांग्रेस इस मुख्य मुद्दे पर विचार करेगी कि माकपा की ताकत कैसे बढ़ाई जाए। उन्होंने वाम एकता को मजबूत करने पर जोर दिया।

बता दें कि इस समारोह में माकपा महासचिव डी. राजा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) लिबरेशन (सीपीआई-माले लिबरेशन) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) महासचिव मनोज भट्टाचार्य और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (एआईएफबी) महासचिव जी. देवराजन भी शामिल हुए।

गौरतलब है कि अखिल भारतीय पार्टी कांग्रेस' सीपीआई (एम) का सर्वोच्च अंग है जिसकी बैठक आमतौर पर हर तीन साल में एक बार सीपीआई (एम) की केंद्रीय समिति द्वारा बुलाई जाती है।निवर्तमान केंद्रीय समिति एक नई केंद्रीय समिति के चुनाव के लिए नामों की सिफारिश करेगी। समिति महासचिव सहित पोलित ब्यूरो के सदस्यों का भी चुनाव करेगी। पिछले साल सीताराम येचुरी के निधन के बाद सीपीआई (एम) महासचिव का पद खाली हो गया था और करात ने पार्टी के अंतरिम समन्वयक के रूप में कार्यभार संभाला था।

अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी करेंगे अपनी संपत्ति की घोषणा

न्यूज़ डेस्क

दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से करोड़ों की नकदी मिले के बाद सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने फैसला किया है कि वे अपनी संपत्ति की सार्वजानिक घोषणा करेंगे। जजों ने यह भी कहा कि न्यायपालिका में ट्रांसपेरेंसी और जनता में भरोसा बनाये रखने के लिए यह बहुत जरुरी है। संपत्ति का ब्योरा वेबसाइट पर लोड की जाएगी। बता दें कि 1 अप्रैल को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में सभी 34 जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की मौजूदगी में अपनी संपत्ति का खुलासा करने का फैसला लिया है।सुप्रीम कोर्ट में जजों की निर्धारित संख्या 34 है। फिलहाल यहां 33 जज हैं, एक पद खाली है। इनमें से 30 जजों ने अपनी संपत्ति का घोषणा पत्र कोर्ट में दे दिया है। हालांकि, इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने के विवाद के बाद लिया गया है। जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में 14 मार्च को आग लगी थी। फायर सर्विस टीम को वहां करोड़ों के अधजले नोट मिले थे।

बता दें कि 1997 में, तत्कालीन सीजेआई जे एस वर्मा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें जजों से अपेक्षा की गई कि वे अपनी संपत्ति की घोषणा चीफ जस्टिस को करें। हालांकि, यह घोषणा सार्वजनिक नहीं की जानी थी।फिर 2009 में, "न्यायाधीश संपत्ति और देनदारियों की घोषणा विधेयक" संसद में प्रस्तुत किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों को अपनी संपत्ति की घोषणा करने कहा गया था। हालांकि, इसमें यह प्रावधान था कि घोषणाएं सार्वजनिक नहीं की जाएंगी। इस प्रावधान के कारण विधेयक को विरोध का सामना करना पड़ा और इसे स्थगित कर दिया गया। 2009 में सूचना के अधिकार के तहत दबाव और पारदर्शिता की बढ़ती मांग के कारण, कुछ जजों ने अपनी मर्जी से संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की। कैश मामले में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आदेश जारी किया गया है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया गया है कि जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक काम न सौंपा जाए। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल जांच कमेटी कर रही है। जिसमें 3 जज हैं। इस कमेटी के सामने जस्टिस यशवंत वर्मा की पेशी जल्द हो सकती है।

वक्फ बिल : बिहार चुनाव में जदयू और लोजपा के लिए बढ़ेगी मुश्किलें

राजनीतिक डेस्क

केंद्र सरकार के वक्फ बिल का समर्थन जदयू ,लोजपा ,टीडीपी और जयंत की पार्टी ने किया है। ये सभी पार्टियां एनडीए में शामिल भी है अजर इस लिहाज से इनका समर्थन कोई नाजायज भी नहीं है। लेकिन ये सभी पार्टियां अपने अपने प्रदेशों में मुस्लिम वोट भी पाते रहे हैं। खासकर बिहार में जदयू चिराग पासवान की लोजपा को हर चुनाव में मुसलमान बड़ी संख्या में वोट डालते रहे हैं। उधर आँध्रप्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलगुदेशम को भी मुसलमानो का बड़ा समर्थन रहा है। अगर इस बार के चुनाव में चंद्रबाबू को मुसलमानो का समर्थन नहीं मिला होता तो न तो उनकी पार्टी सत्ता तक पहुँचती और न ही वे सीएम की कुर्सी तक पहुँच पाते। कह सकते हैं कि ये पार्टियां मुसलमानो को साधती रही है। लेकिन वक्फ बिल संशोधन मसले पर ये पार्टियां मुसलमानो के खिलाफ जाकर सरकार के साथ खड़ी हो गई। अब इसका राजनीतिक अंजाम क्या होगा यह देखने की बात होगी। चुकी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते इसलिए बीजेपी पर उनकी नाराजगी का कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन नीतीश कुमार ,चंद्रबाबू नायडू ,चिराग पासवान और जयंत चौधरी जो मुसलमानों की राजनीति करते रहे हैं उनकी आगे की राजनीति का क्या होगा यह अब चर्चा का विषय बन गया है।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने सभी नेताओं को चुनौती दे डाली है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि मुस्लिम चारों को कभी माफी नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम विरोध बिल का समर्थन किया है।

असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को खुलेआम चुनौती और धमकी देते दिख रहे हैं। वीडियो में वो कह रहे हैं, "नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान, या रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम जो हमारी शरीयत पर हमला करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, हम कभी माफ नहीं करेंगे। " ओवैसी के इस बयान को बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि अगले 5 महीने के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। वक्फ बिल को आरजेडी अपना हथियार बनाने में जुट गई है। अब ओवैसी भी इसको लेकर एनडीए गठबंधन को सबक सिखाने की तैयारी में हैं।

ओवैसी ने जिस तरह से नीतीश और चिराग को बिहार चुनाव की याद दिलाते हुए सबक सिखाने की धमकी दी है। बिहार के सीमांचल में मुस्लिमों की संख्या अधिक है। वहां ओवैसी की पार्टी का दबदबा रहा है। उसे ओवैसी का गढ़ माना जाता है। आगामी बिहार चुनाव में ओवैसी का पूरा फोकस सीमांचल पर होगा। पूरे राज्य में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी ओवैसी कर रहे हैं। बिहार चुनाव में ओवैसी जनता के सामने वक्फ बिल के खिलाफ जनता के पास जाएंगे और उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। नीतीश और चिराग के लिए बिहार चुनाव में ओवैसी बड़ी परेशानी बन सकते हैं।

लोकसभा ने बुधवार देर रात विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के कड़े विरोध के बीच वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित कर दिया। जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधनों को अपनी मंजूरी दी। इस बिल पर फिलहाल राज्यसभा में गरमा-गर्म बहस जारी है। राज्यसभा से बिल पास होने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद बिल कानून का रूप ले लेगा।

बिहार का धनकुबेर इंजीनियर तारिणी दास

न्यूज़ डेस्क

बिहार में डबल इंजन की सरकार लम्बे समय से चल रही है। सीएम नीतीश कुमार की की छवि साफ़ सुथरी बताई जाती है और संभव है कि वे ऐसा होंगे भी। लेकिन बिहार में पिछले कुछ सालों में जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं उससे तो साफ़ लगता है कि सत्ता और प्रशासन मिलकर बिहार को चुना लगा रहे हैं। लूट रहे हैं। इधर केंद्र में मोदी की सरकार है। बीजेपी वाले कहते हैं कि भ्रष्टाचार हम सहन नहीं करते। पीएम मोदी कहते हैं कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। लेकिन बिहार में जो हो रहा है वह तो इन बयानों को भ्रमित करते हैं।

अभी हाल में ही बिहार सरकार ने भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास को बर्खास्त कर दिया गया है । प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी में उनके ठिकानों से करोड़ों रुपये कैश बरामद हुए थे। इतने कैश की गिनती के लिए चार मशीन मंगाए गए। ये नकदी तारिणी दास के घर से बरामद हुए हैं। तारिणी दास को सेवानिवृत्ति के बाद दो साल का सेवा विस्तार मिला था, लेकिन काले धन की बरामदगी के बाद सरकार ने तत्काल प्रभाव से उनका नियोजन रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

ईडी की जांच में भवन निर्माण विभाग और सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में टेंडर मैनेज करने के नाम पर बड़े पैमाने पर घूसखोरी का खुलासा हुआ है। आरोप है कि ठेकेदारों से बिल पास करने के एवज में मोटी रकम वसूली जा रही थी। ईडी को मिले दस्तावेजों के आधार पर जिन अन्य अधिकारियों के ठिकानों से कम नकदी मिली है, उनकी आय और संपत्तियों की जांच भी जारी है। गौरतलब है कि ईडी ने हाल ही में चीफ इंजीनियर तारिणी दास समेत सात लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 11.64 करोड़ रुपये कैश बरामद किए गए। यह कार्रवाई आईएएस संजीव हंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई।

अब कोई भी कह सकता है कि जब एक इंजीनियर के यहाँ से इतनी नकदी मिल सकती है तो इनके आका बड़े नेताओं और मंत्रियों के पास कितनी नकदी होगी। 90 के दशक में लालू यादव समेत कई नेताओं पर चारा घोटाला का मामला दर्ज हुआ था। लालू यादव आज भी उस दंश से उबरे नहीं है। ऐसे में जिस विभाग के लोग इतनी बड़ी डकैती किये हैं क्या उनके मंत्रियों पर कोई कार्रवाई होगी ?

कपिल सिब्बल ने क्यों कहा कि वक्फ बिल का असर बिहार पर पड़ेगा?

न्यूज़ डेस्क

वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से पास होने पर विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक, जनविरोधी और राजनीति से प्रेरित बताया है। कपिल सिब्बल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार के पास लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत था, लेकिन यह बिल देश में विभाजन को दर्शाता है।उन्होंने बताया कि वोटिंग में 128 पक्ष में और 94 खिलाफ वोट पड़े, जिससे साफ है कि बड़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया। सिब्बल ने कहा कि इसका असर बिहार जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों पर पड़ेगा, जहां विपक्ष को फायदा हो सकता है। उन्होंने इसे समाज को बांटने वाली राजनीति का हिस्सा बताया और कहा कि यह बिल गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दों को हल नहीं करेगा।उनके मुताबिक, यह एक राजनीतिक चाल है, जिससे विवाद बढ़ेगा और सरकार को लगता है कि इससे उसे फायदा होगा। सिब्बल ने चेतावनी दी कि यह देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है।

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे विपक्ष की नैतिक जीत करार दिया। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा में बिल के खिलाफ 35 वोटों का अंतर था और राज्यसभा में अंतर कम था।सिंघवी ने इसे जनादेश के खिलाफ बताया और कहा कि सरकार ने अपने बहुमत का दुरुपयोग करके इसे जबरदस्ती थोपा है। उन्होंने दावा किया कि अगर बिल को कोर्ट में चुनौती दी गई, तो इसके असंवैधानिक होने की पूरी संभावना है, खासकर संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत। सिंघवी ने यह भी कहा कि यह बिल मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता को नष्ट करता है और समाज में अविश्वास पैदा करेगा।उनके मुताबिक, यह जनता के मूड के खिलाफ है और इसमें व्यापक समर्थन की कमी है। राजद नेता मनोज झा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसी संसद में पहले किसान कानून भी पास हुए थे, जिन्हें बाद में वापस लेना पड़ा।झा ने सरकार पर बहुमत के अहंकार का आरोप लगाया और कहा कि संख्या बल होने का मतलब यह नहीं कि हर ज्ञान सरकार के पास ही है। उन्होंने इसे गैर-जरूरी और विभाजनकारी बताया। झा ने कहा कि राज्यसभा में सरकार का बहुमत बहुत मजबूत नहीं था, फिर भी उसने इसे पास करवाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जनता की नाराजगी को दूर नहीं किया गया, तो इस बिल का हश्र भी किसान कानूनों की तरह हो सकता है। झा ने सरकार से आत्ममंथन करने और संजीदगी दिखाने की अपील की।

झारखंड में फिर बढ़ी ईडी की सक्रियता

न्यूज़ डेस्क

झारखंड में ईडी की सक्रियता फिर से बढ़ गई है। इस बार ईडी सीधे नेताओं पर छापा नहीं मार रही है। उसके रडार पर कई अधिकारी हैं। जानकारी के मुताबिक़ ईडी के रडार पर कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और कई इस तरह की शिकायत भी दर्ज की गई है कि जिनमे नेताओं के साथ मिलकर अधिकारी लूट कर रहे थे। प्रर्वतन निदेशालय ने पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के आप्त सचिव और राजधानी के दो ठिकानों समेत देश के कुल 21 इलाकों में छापा मारा है। ये कार्रवाई आयुष्मान भारत योजना घोटाले में की गयी है। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित अरविंद मार्ग के रश्मि एनक्लेव और रामेश्वरम लेन के श्यामा एनक्लेव में थर्ड फ्लोर पर रहने वाले सुजीत यादव के ठिकानों पर यह रेड पड़ा है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं।

आयुष्मान घोटाला से संबंधित मामले में ईडी ने जमशेदपुर के एनएच-33 मार्ग के बिग बाजार से पीछे स्थित नीलगिरी कॉलोनी में बन्ना गुप्ता के आप्त सचिव ओम प्रकाश सिंह गुड्डू के ठिकानों पर छापा मारा है। जमशेदपुर के कई इलाकों पर प्रवर्तन निदेशालय ने रेड मारी है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

दरअसल ईडी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड में हुई गड़बड़ियों को लेकर दर्ज ईसीआईआर की जांच शुरू की है। कुछ दिन पहले सीएजी रिपोर्ट में इसका खुलासा भी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि कुछ अस्पताल फर्जी मरीजों का इलाज कर करोड़ों की राशि का भुगतान ले लिया। यहां तक कि कई ऐसे लोगों के नाम पर बिल बना दिया गया जिसकी पहले ही मौत हो चुकी है। इसके बाद प्रर्वतन निदेशालय ने झारखंड स्टेट हेल्थ सोसाइटी और स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। ऐसी संभावना जतायी जा रही है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की और शुक्रवार को संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर छापा मार दिया. कुल 200 से अधिक अस्पताल, इंश्योरेंस और दवा कंपनियां जांच के दायरे में है।

चारो तरफ से घिरे नक्सली अब युद्ध विराम को तैयार

न्यूज़ डेस्क

सुरक्षा बलों के सामने लगातार कमजोर पड़ते नक्सली अब सरकार के सामने युद्ध विराम की गुहार लगा रहे हैं। नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी ने छत्तीसगढ़ सरकातर से मांग की है कि सरकार यदि ऑपरेशन बंद करने का घोषणा करती है तो नक्सली भी युद्ध विराम को तैयार है। उल्लेखनीय है कि बीते कुछ महीनों से सुरक्षाबलों की टीम लगातार ऑपरेशन चला रही है। जिसमें कई बड़े खूंखार नक्सली लीडर्स को जवानों ने ढेर कर दिया है।

बता दें कि सीपीआई माओवादी केंद्रीय समिति का हालिया बयान उनके प्रवक्ता अभय द्वारा जारी किया गया है। बयान में तत्काल युद्ध विराम और शांति वार्ता की मांग की गई है, जिसमें भारत सरकार से ऑपरेशन को रोकने का आग्रह किया गया है। उनका दावा है कि इसके कारण आदिवासी समुदायों के खिलाफ काफी हिंसा हुई है। वे सुरक्षा बलों की वापसी और आतंकवाद विरोधी अभियानों को रोकने की मांग की हैं।

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ में व्यापक स्तर पर नक्सल विरोधी अभियान चलाये जा रहे हैं। इस अभियान में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। लगातार नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि छत्तीसगढ़ का पूरा अबूझमाड़ जंगल अब सुरक्षाबलों के रडार पर है और वहां अब पुलिस की पहुँच भी हो गई है। इसी इलाके में नक्सली अपना ठौर ठिकाना बनाये हुए हैं और इसी घने जंगल में इनका ट्रेनिंग भी चलता रहा है। लेकिन अब ये काफी कमजोर होते जा रहे हैं। अपने लिखित बयान में नक्सली संगठन ने सरकार से जो मांग की है वह काफी अहम है। नक्सलियों ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर माओवादी-प्रभावित क्षेत्रों को लक्षित करते हुए 'कागर' नामक एक गहन आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया।इस अभियान के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर हिंसा, हत्याएं और सामूहिक गिरफ्तारियां हुई हैं।हताहतों की संख्या और मानवाधिकार उल्लंघन।400 से अधिक माओवादी नेता, कार्यकर्ता और आदिवासी नागरिक कथित तौर पर मारे गए हैं। महिला माओवादियों को कथित तौर पर सामूहिक यौन हिंसा और फांसी का सामना करना पड़ा है। कई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें अवैध हिरासत और यातना दी गई है। ऐसे में नक्सली शांति वार्ता चाहते हैं और युद्ध विराम की बात करते हैं।

शांति वार्ता के लिए माओवादियों की कुछ शर्तें भी रखी हैं। जैसे प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों से सुरक्षा बलों की तत्काल वापसी। नई सैन्य तैनाती का अंत। आतंकवाद विरोधी अभियानों का निलंबन। सरकार के खिलाफ आरोप। सरकार पर क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने के लिए आदिवासी समुदायों के खिलाफ "नरसंहार युद्ध" छेड़ने का आरोप है। और नागरिक क्षेत्रों में सैन्य बलों के उपयोग को असंवैधानिक बताया गया है। माओवादियों ने बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार संगठनों, पत्रकारों, छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं से शांति वार्ता के लिए सरकार पर दबाव बनाने का आग्रह किया।वार्ता के लिए गति बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का अनुरोध किया गया। अगर सरकार उनकी पूर्व शर्तों पर सहमत होती है तो वे बातचीत में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सीपीआई (माओवादी) ने कहा कि जैसे ही सरकार सैन्य अभियान बंद करेगी, वे युद्ध विराम की घोषणा करेंगे।

मोनालिसा का टूटा हीरोइन बनने का सपना

न्यूज़ डेस्क

मध्यप्रदेश खरगोन की रहने वाली महाकुम्भ मेले में अचानक वायरल हो गई थी। वह पहुंची थी माला बेचने लेकिन वह स्टार बन गई। उसकी खूबसूरती ने मीडिया में बबाल मचा दिया था। फिल्मकार सनोज मिश्रा की नजर मोनालिसा पर गई और वह मोनालिसा को लेकर द डायरी ऑफ़ मणिपुर फिल्म बनाने को तैयार हो गए। देखते -देखते मोनालिसा मुंबई पहुँच गई। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई। उसके सपने पुरे होने ही वाले थे कि एक रेप केस में फिल्मकार सनोज मिश्रा पकडे गए और मोनालिसा का सपना टूट गया।

महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा को अपने अपकमिंग फिल्म में साइन करने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने रेप केस के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सनोज मिश्रा पर एक युवती को फिल्म में काम दिलाने का लालच देकर उसके साथ शारीरिक शोषण करने का आरोप है। इसके अलावा सनोज पर पीड़िता का तीन बार गर्भपात कराने के भी गंभीर आरोप लगे हैं।

बता दें कि मोनालिसा के इंस्टाग्राम से एक वीडिया पोस्ट हुआ, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मोनालिसा फूट-फूटकर रोती नजर आ रही हैं। इस दैरान उनके परीजन उन्हें संभालते दिख रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी के चलते मानालिसा रो रही हैं। सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद वायरल गर्ल के हीरोइन बनने का सपना टूटता नजर आ रहा है।

अभी हाल ही में प्रोड्यूसर वसीम रिजवी ने एक इंटरव्यू के दौरान सनोज मिश्रा को अय्याश बताया था। वसीम रिजवी ने कहा था कि सनोज मिश्रा शराब के शौकीन हैं और पीने के बाद इन्हें लड़कियां चाहिए होती हैं। सनोज मिश्रा मोनालिसा की मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं। अगर मोनालिसा के परिवार को डायरेक्टर सनोज मिश्रा की सच्चाई पता होती, तो वह कभी अपनी बेटी को उसके हवाले नहीं करते।

मध्यप्रदेश में जिलाध्यक्षों को काफी ताकतवर बना रहे राहुल

न्यूज़ डेस्क

मध्यप्रदेश विधान सभा का चुनाव हालांकि 2028 में होंगे लेकिन कांग्रेस अभी से ही जमीनी स्तर पर संगठन को धार देने में जुटी हुई है। प्रदेश कांग्रेस को नए सिरे से मजबूत करने के लिए मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को राहुल गांधी ने कई तरह की सलाह भी दी है ताकि आने वाले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी जाए। मजबूत संगठन के लिए राहुल गांधी ने जो कहा है वह काफी अहम है। राहुल गांधी ने जीतू पटवारी को कहा है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति फिर से की जाए और ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जिनकी इलाके में पहचान है और जो बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करने में सक्षम भी हैं। राहुल गाँधी के इस सन्देश के बाद सूबे के सभी जिला अध्यक्षों का बदलना अब तय माना जा रहा है। जीतू पटवारी इस दिशा में तेजी से काम भी का रहे हैं। इसी सप्ताह सभी जिला अध्यक्षों के साथ दिल्ली में राहुल गांधी की मुलाकात भी होनी है जिसमे कई तरह रणनीतिक बातें राहुल गांधी कर सकते हैं।

एमपी में लगातार चुनावी हार झेल रही कांग्रेस अब जिला लेवल से संगठन को मजबूत करने की तैयारी में है। इसलिए इसी सप्ताह दिल्ली में राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों की मीटिंग होने वाली है, जिसमें कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। इस बैठक में जिलाध्यक्षों के अलावा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और कांग्रेस के सीनियर नेता भी शामिल होंगे।

कांग्रेस का मानना है कि पार्टी को फिर से मजबूती देने के लिए उसे जिला लेवल से मजबूत करना होगा। इसलिए संगठन में इस बात की चर्चा तेज है कि जिला अध्यक्षों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाएं, क्योंकि उनका फीडबेक ही पार्टी के सबसे ज्यादा काम आ सकता है। एआईसीसी ने जिला संगठनों को मजबूत बनाने पर जोर देने की बात कही है। बताया जा रहा है कि आने वाले चुनावों में जिलाध्यक्षों के पास पार्षद से लेकर सांसद तक के टिकट बांटने में अहम भूमिका रहेगी। क्योंकि जिले की सबसे सटीक जानकारी जिलाध्यक्ष के पास ही हो सकती है, ऐसे में किसे टिकट दिया जाना चाहिए और किसे नहीं यह भोपाल या दिल्ली से तय न होकर संबंधित जिले से ही तय किया जाएगा। चुनाव समिति की बैठक में जिलाध्यक्षों की राय को महत्व दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बैठक में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी।

बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने जीतू पटवारी को नए जिलाध्यक्षों के चयन के लिए भी हरी झंडी दे दी है। जिसके बाद जीतू पटवारी जल्द ही नए जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां कर सकते हैं। जो जिलाध्यक्ष पिछले तीन सालों से जमे हैं, उनकी छुट्टी होना तय मानी जा रही है। इसके अलावा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कुछ गाइडलाइन भी बनाई गई हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष की उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा उसे पार्टी में काम करने का 10 से 15 साल का अनुभव होना चाहिए। जिलाध्यक्ष तकनीक का जानकार हो और सोशल मीडिया पर लगातार उसकी सक्रियता होनी चाहिए। क्योंकि कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच समन्वय बनाने में सोशल मीडिया की भी अहम भूमिका रहती है। . कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक इस बार अहमदाबाद में होने जा रही है, जिसमें जिलाध्यक्षों को पावर देने वाले प्रस्ताव को पास किया जा सकता है, इसके बाद इसे सभी प्रदेशों की कांग्रेस कमेटी में लागू किया जाएगा।

राजस्थान सिवाना की पहाड़ियों में मिला दुर्लभ खनिज सम्पदा

भारत चीन से 700 टन के करीब आयात हर साल कर रहा है। इसके अलावा हांगकांग, जापान, अमेरिका, इंग्लैण्ड, स्वीडन, सिंगापुर, स्वीडन मंगोलिया से कम मात्रा में आयात कर रहा है।

न्यूज़ डेस्क

राजस्थान के नए जिले बालोतरा में लंबे समय से सिवाना की पहाडियों में दुर्लभ खनिज की खोज की प्रमाणिकता सिद्ध हो गई है।जानकारी के मुताबिक़ यहाँ 1 लाख 11 हजार 845 टन दुर्लभ खनिज मौजूद है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने इसकी घोषणा की है। राज्य में 35 दुर्लभ खनिज परियोजनाएं और 195 खोज परियोजनाओं में अब बालोतरा के सिवाना इलाका शामिल है। चीन की मॉनोपोली तोड़ने वाले इन खनिजों पर अब अन्वेषण से आगे तक परमाणु ऊर्जा विभाग कार्य कर रहा है।

बता दें कि बाड़मेर जिले के सिवाना में रेअर अर्थ का बड़ा खजाना होने के संकेत एक दशक पहले ही मिले थे। परमाणु ऊर्जा विभाग ने वर्ष 2021-22 से इस पर कार्य प्रारंभ किया। इसमें जी-4(प्रारंभिक अन्वेषण) और जी-3(संसाधन जुटाने के आगामी स्तर) तक कार्य चल रहा है। जयपुर ग्रामीण के सांसद राव राजेन्द्र सिंह ने कोयला मंत्री से संसद में जानकारी चाही। इस पर कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने जवाब में बताया कि परमाणु ऊर्जा विभाग ने राजस्थान के बालोतरा जिले के कुछ हिस्से में कठोर चट्टानी इलाके में 1 लाख 11 हजार 845 टन दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड(आरईओ) की खोज की है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत इस पर कार्य हो रहा है।सामरिक और महत्वपूर्ण खनिजों की क्षमता को लेकर अभी राज्य में 35 परियोजनाएं और 195 अन्वेषण का कार्य चल रहा है।

अभी तक चीन की इस दुर्लभ धातु पर मॉनोपोली है। भारत चीन से 700 टन के करीब आयात हर साल कर रहा है। इसके अलावा हांगकांग, जापान, अमेरिका, इंग्लैण्ड, स्वीडन, सिंगापुर, स्वीडन मंगोलिया से कम मात्रा में आयात कर रहा है। भारत का कुल आयात 1185 टन है।

अब पंजाब को नशामुक्त करेंगे केजरीवाल

न्यूज़ डेस्क

पंजाब नशे की चपेट में है। पंजाब को नशा से मुक्त करने के लिए एक तरफ राज्य के राज्यपाल पदयात्रा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी की राजनीतिक मनसा को भांपते हुए आप नेता केजरीवाल ने ऐलान किया है कि आप की पंजाब सरकार नशा मुक्ति को लेकर बड़ा अभियान चलाएगी। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब से नशे को खत्म करने के लिए पार्टी के मिशन मोड पर काम कर रही है और यह हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य भी है और प्रतिबद्धता भी।

केजरीवाल ने कहा है कि राज्य को नशीली दवाओं के चंगुल से मुक्त करने के लिए पंजाब के प्रत्येक व्यक्ति को पार्टी एकजुट करेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केजरीवाल ने नशा को ख़त्म करने की कसम भी खाई और सभी पार्टी नेताओं को भी शपथ दिलाई। सभी ने एक स्वर में कहा कि, 'मैं पंजाब की मिट्टी का सच्चा सपूत हूं। मैं आम आदमी पार्टी का सच्चा स्वयंसेवक हूं। आज मैं पंजाब की मिट्टी की कसम खाता हूं कि मैं खुद कभी नशा नहीं करूंगा, मैं अपने दोस्तों, परिवार और समाज को नशे से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जहां भी मुझे नशा बिकता दिखेगा, मैं पुलिस को सूचित करूंगा। मैं डरूंगा नहीं क्योंकि इस लड़ाई में भगवान मेरे साथ हैं। मैं विकास को चुनूंगा, विनाश को नहीं। मैं मौन नहीं, क्रांति चुनूंगा। मैं कसम खाता हूं कि जब तक पंजाब नशे से मुक्त नहीं हो जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा।'

केजरीवाल ने कहा कि पिछले एक महीने में नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए अभूतपूर्व कार्रवाई की गई है। ऐसा पिछले 75 वर्षों में किसी ने नहीं देखा है। केवल एक महीने में हजारों ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये वही तस्कर हैं जिनके नाम से लोगों की रूह कांप जाती थी। केजरीवाल ने ड्रग तस्करों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अगर कोई पुलिस से मुठभेड़ में भिड़ने की हिम्मत करेगा, तो पुलिस कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएगी।केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर अपने प्रयास जारी रखने का आग्रह करते हुए कहा कि अगर नशे के सौदागर उनके गांव में नशा बेचने आएं तो उन्हें मत आने दीजिए। उनसे डरिए मत, क्योंकि पुलिस और प्रशासन आपके साथ है।

केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि 1 अप्रैल से पार्टी हर गांव में अपनी यात्रा शुरू करेगी। हालांकि, फसल के मौसम के कारण वे इसे एक महीने के लिए स्थगित कर रहे हैं लेकिन कल से हम स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ शहरों में पदयात्रा शुरू करेंगे, जहां लोग खुद नशीली दवाओं का उपयोग न करने और यह सुनिश्चित करने की शपथ लेंगे कि कोई भी पंजाब में नशीली दवाएं न बेच पाए।

रेप केस में पादरी बजिंदर सिंह को उम्र कैद

न्यूज़ डेस्क

मोहाली की पॉक्सो कोर्ट ने स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते बजिंदर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी करार दिया था।

इस पादरी पर एक महिला के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप थे। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह कड़ा फैसला सुनाया है। सजा के ऐलान के बाद पीड़ितों ने राहत की सांस ली, वहीं बचाव पक्ष ने उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है।

यह मामला तब सुर्खियों में आया था, जब एक महिला ने बजिंदर सिंह पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया था। पीड़िता ने दावा किया था कि पादरी ने मोहाली स्थित अपने घर पर उसके साथ बलात्कार किया और इस घटना को रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी।महिला के अनुसार, "आरोपी ने उसे धमकाया था कि अगर

वह उसकी मांगों को नहीं मानती तो वह वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वायरल कर देगा। '' मोहाली की पॉक्सो कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल ले जाया गया। हरियाणा के यमुनानगर निवासी और जालंधर स्थित 'चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम' के संस्थापक बजिंदर सिंह खुद को ईसा मसीह का दूत बताता है और चमत्कारिक इलाज का दावा करता है। उसके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें वह मरीजों को ठीक करता दिखाई देता है। हालांकि, अब, बजिंदर सिंह की सजा के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

क्या वक्फ बिल के बहाने अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है सरकार?

न्यूज़ डेस्क

वक्फ संशोधन बिल-2025 गुरुवार को लोकसभा में पास हो गया। अब राजयसभा की बारी है। संभव है यहाँ भी पास हो जाए। लेकिन इस बिल को लेकर देश भर में चर्चा गर्म है। इसके राजनीतिक असर की बात की जा रही है। राजस्थान में भी इस बिल को लेकर खूब चर्चा चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वक्फ बिल पर बोलते हुए कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। उन्होंने केंद्र के वक्फ संशोधन बिल को भी इसी रणनीति का हिस्सा बताया। गहलोत ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, शेयर बाजार में गिरावट और रुपए के अवमूल्यन जैसे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार बार-बार अल्पसंख्यक वर्ग को निशाने पर लेने वाले कानून बना रही है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स ' पर एक पोस्ट में कहा वक्फ से जुड़े कानून को अनावश्यक बताया। साथ ही आरोप लगाया कि इस कानून की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इसे लाकर बहुसंख्यक समाज का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने और अल्पसंख्यक समाज में भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

गहलोत ने कहा कि सरकार का उद्देश्य दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ाना है। इस तरह के कानून सिर्फ समाज में तनाव पैदा करने के लिए लाए जा रहे

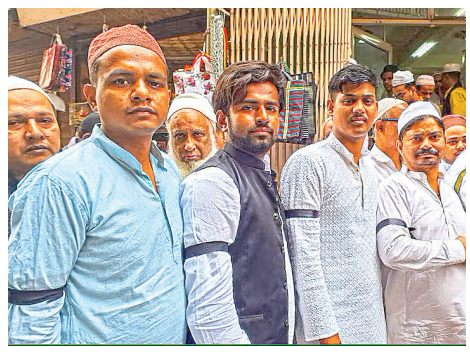

हैं। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून का हवाला देते हुए कहा कि यह कानून 2020 में बना दिया गया, लेकिन इसके नियम 2024 में बनाए गए। इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसे बार-बार उछाला गया और पूरे देश में तनाव पैदा किया गया।

राजस्थान के मुसलमान भी बीजेपी को वोट नहीं डालते हैं। हालाँकि ब्ज्प इस समाज के बीच खूब जाती है अजर कई तरह की बागतें भी करती रही है लेकिन सच यही है कि मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं मिलते। यहाँ के मुसलमान कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दलों को अपना वोट देते हैं। ऐसे में अब वक्फ बिल अबग्र पास हो जाता है और यह लागु भी हो जाता है तो बीजेपी भविष्य के लिए भी मुस्लिम राजनीति से बीजेपी वंचित हो सकती है।

न्यू देहली पोस्ट

13 अप्रैल 2025

एआईएडीएमके एनडीए खेमे में लौटने को उत्सुक

राजनीतिक डेस्क

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच 25 मार्च को नयी दिल्ली में हुई। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो गई है कि फिर सुविधा के मुताबिक़ अन्नद्रमुक और बीजेपी के साथ गठजोड़ हो सकता है। पलानीस्वामी ने इस बात से इनकार किया कि इस मुलाकात का उनकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच नये सिरे से गठबंधन से कोई लेना-देना था, लेकिन मुलाकात के बाद अमित शाह की सोशल मीडिया पोस्ट ने कुछ और ही इशारा किया। शाह ने उम्मीद जतायी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए अगले साल तमिलनाडु में सरकार बनायेगा। इसने विधानसभा चुनाव 2026 से पहले एआईएडीएमके-भाजपा गठबंधन के पुनर्जीवित होने की अटकल को हवा दी।

बता दें कि आम चुनाव 2019 और विधानसभा चुनाव 2021 में गठबंधन में रहीं भाजपा और एआईएडीएमके ने आम चुनाव 2024 से पहले अपने रास्ते अलग कर लिये थे । एआईएडीएमके ने भाजपा के तमिलनाडु अध्यक्ष के. अन्नामलाई द्वारा बार-बार उकसावों का हवाला दिया, जिन पर उसने अपनी पार्टी के 'आइकनों' के अपमान का आरोप लगाया था। मुसलमानों और ईसाइयों के बड़े हिस्से के बीच दोबारा समर्थन हासिल होने की उम्मीद में, एआईएडीएमके ने मतदाताओं के सामने अकेले जाने का निर्णय लिया। लेकिन चुनावी परिणाम अनुकूल नहीं रहे।

डीएमके-नीत गठबंधन ने तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटें जीत लीं, जबकि अलग-अलग लड़ रहीं एआईएडीएमके और भाजपा के गठबंधनों ने एक दूसरे की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कम-से-कम 13 सीटों पर एक दूसरे का वोट काटा। इससे भी बुरा यह रहा कि एआईएडीएमके को सात निर्वाचन क्षेत्रों में जमानत जब्त होने का अपमान सहना पड़ा। बीते 47 सालों में 30 साल तक राज्य की सत्ता में रही पार्टी के लिए यह ऐतिहासिक निचला स्तर था। फिर भी, पलानीस्वामी ने यह दावा जारी रखा कि उनकी पार्टी साल 2026 में भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने साल 2023 में औपचारिक अलगाव के बाद से यही रुख बनाये रखा।

चुनावी अंकगणित से परे, राजनीतिक हालात ने एआईएडीएमके और भाजपा दोनों को सुलह के लिए धीरे-धीरे मजबूर किया। डीएमके-नीत गठबंधन स्थिर लगता है और उसमें आंतरिक विक्षोभ का कोई लक्षण दिखायी नहीं पड़ता। इस दरम्यान, अभिनेता विजय द्वारा नयी शुरू की गयी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' और सीमान की 'नाम तमिलर काची' ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी है, जिससे वह राजनीतिक अलगाव में चली गयी है। इस संदर्भ में, एआईएडीएमके और भाजपा दोनों को अपनी साझेदारी पुनर्जागरण करने में रणनीतिक मूल्य दिख रहा है। एआईएडीएमके के लिए, तात्कालिक लक्ष्य दोबारा सत्ता पाना है। भाजपा के लिए, तमिलनाडु में अपनी मौजूदगी के विस्तार की खातिर एआईएडीएमके के साथ गठबंधन सबसे व्यावहारिक रास्ता है क्योंकि इस राज्य में उसकी स्वतंत्र मौजूदगी अब भी सीमित है। हालांकि, सुविधावाद के आधार पर बने गठबंधनों का नतीजा शायद ही कभी लोक कल्याण पर केंद्रित नीतियों के रूप में सामने आता है। दोनों पार्टियों को यह जन विश्वास बढ़ाने के लिए और काम करना होगा कि वे इस चिंताजनक पैटर्न को उलट सकेंगी।

रंग और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ केरल में फिर से बहस

न्यूज़ डेस्क

केरल की मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन ने रंगभेद को लेकर एक लंबे समय से चली आ रही बहस को फिर से हवा दे दी। रंगभेद का सामना करने के बाद उन्होंने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया, जिसके बाद उनकी पोस्ट पर जमकर बहस हो रही है। एनडीटीवी से बात करते हुए शारदा ने कहा कि काले रंग को लेकर आम धारणा को बदलने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, "हमें यह फिर से परिभाषित करना होगा कि काला रंग क्या है, क्योंकि जब तक हम इसकी सुंदरता को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ये सवाल ऐसे ही बना रहेगा। " 1990 बैच की आईएएस अधिकारी शारदा मुरलीधरन ने हाल ही में एक फेसबुक पोस्ट में अपने रंग को लेकर की गई टिप्पणियों का जवाब दिया था। इन टिप्पणियों में उनके काले रंग को उनकी कार्यक्षमता से जोड़कर तंज कसा गया था। शारदा ने बताया कि यह अनुभव उनके लिए "दिलचस्प" था। उन्होंने कहा कि बचपन से ही उन्हें अपनी सांवले रंग को लेकर कमेंट सुनने पड़े हैं, लेकिन इस बार उनकी तुलना उनके पति और पूर्व मुख्य सचिव वी. वेणु के कार्यकाल से की गई। शारदा मुरलीधरन ने अपना अनुभव शेयर करते हुए मेरे लिए यह देखना दिलचस्प था कि दोनों को एक रंग के पैमाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस टिप्पणी में लैंगिक भेदभाव का भी एक आयाम था। अपनी पोस्ट में उन्होंने एक टिप्पणी का जिक्र किया था जिसमें उनके प्रदर्शन को लेकर कहा गया था, "यह उतना ही काला है जितना मेरे पति का कार्यकाल गोरा था। "

अपनी पोस्ट में शारदा ने काले रंग की खूबसूरती को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, "काला रंग ब्रह्मांड की सर्वव्यापी सच्चाई है. काला वह रंग है जो सब कुछ सोख सकता है, यह मानव जाति के लिए जानी जाने वाली सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतीक है। यह वह रंग है जो हर किसी पर जंचता है- ऑफिस की ड्रेस कोड हो, शाम की चमकदार पोशाक हो, काजल की गहराई हो या बारिश की उम्मीद। " शारदा मुरलीधरन की इस पोस्ट ने न केवल रंगभेद के मुद्दे को उजागर किया, बल्कि समाज में गहरे बैठे रंग के प्रति पक्षपात पर एक खुली चर्चा की जरूरत को भी रेखांकित किया है। उनकी इस पहल को सोशल मीडिया पर व्यापक समर्थन मिल रहा है और लोग इसे एक साहसिक कदम बता रहे हैं।

कर्नाटक कांग्रेस में फुट पड़ने की सम्भावना

न्यूज़ डेस्क

कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिला है, जितना पिछले कई चुनावों में किसी एक पार्टी को नहीं मिला। कई चुनावों से तो गठबंधन की ही सरकार बन रही थी लेकिन मई 2023 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटें मिलीं और भाजपा काफी पीछे छूट गई। हालांकि बाद में भाजपा और जेडीएस में तालमेल हुआ तो दोनों को मिला कर 84 सीटें हैं और कांग्रेस को अकेले 138 सीट है। 224 सदस्यों की विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 113 का है। यानी कांग्रेस 25 सीट आगे है और भाजपा गठबंधन 29 सीट पीछे है। फिर भी पहले दिन से सरकार की अस्थिरता का मामला चलता रहता है। इसके पीछे यह भी कहा जाता है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ढाई साल के बाद मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करेंगे और तब कांग्रेस में फूट हो सकती है।

इस बीच एक नई राजनीति देखने को मिली है। डीके शिवकुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कांग्रेस के नेताओं में से एक सतीश जरकिहोली ने पिछले दिनों जेडीएस नेता और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान एचडी देवगौड़ा भी मौजूद थे। गौरतलब है कि सतीश जरकिहोली राज्य सरकार में मंत्री हैं और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के प्रति निष्ठावान माने जाते हैं। बेलगावी के जरकिहोली बंधु कांग्रेस और भाजपा दोनों से जुड़े हुए हैं और हर बात की सत्ता पलट में उनका हाथ होता है। जरकिहोली बंधुओं का कुनबा पांच भाइयों का हैं और पांचों विधायक या विधान पार्षद हैं। बहरहाल, सतीश जरकिहोली की कुमारस्वामी से मुलाकात ने कर्नाटक की राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है। अगले कुछ महीने राज्य की राजनीति के लिए बहुत अहम होंगे।

काशी के घाटों पर इवेंट के लिए देनी होगी फीस

न्यूज़ डेस्क

वाराणसी के किसी भी घाट पर अगर आप कोई इवेंट करते हैं तो आपको उसकी फीस चुकानी होगी। वाराणसी नगर निगम ने नए कानून के तहत शुल्क की घोषणा कर दिया है। बड़ी बात यह बही है कि अगर आप कोई इवेंट करना चाहते हैं तो इसकी सूचना नगर निगम को 15 दिन पहले देनी होगी। स्वीकृति मिलने के बाद आपको फीस जमा करनी होगी। तभी आप कोई इवेंट कर सकते हैं।

नगर निगम की तरफ से कहा गया है कि अब तक काशी के घाटों पर किसी भी सांस्कृतिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम के लिए नगर निगम को केवल सूचना देनी होती थी, लेकिन अब इसके लिए शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। नगर निगम के अनुसार, किसी भी संस्था या व्यक्ति को घाटों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 880 रुपए प्रति वर्ग मीटर शुल्क देना होगा।

नगर निगम ने प्रक्रिया को डिजिटल करते हुए स्मार्ट काशी मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन करने का नियम बनाया है। इच्छुक आयोजकों को कार्यक्रम से 15 दिन पहले आवेदन करना होगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद ही आयोजन की अनुमति मिलेगी।

बता दें कि घाटों पर लगातार बढ़ते आयोजनों के कारण गंदगी, तोड़फोड़ और रखरखाव की समस्याएं बढ़ रही थीं। घाटों के बेहतर रखरखाव और सुव्यवस्थित संचालन के लिए यह नियम लागू किया गया है। नगर निगम ने गंगा उपविधि तैयार की है, जिसके तहत गंगा घाटों के क्षेत्र को संरक्षित करने और साफ-सफाई बनाए रखने के लिए यह शुल्क प्रणाली लागू की गई है। अब काशी के घाटों पर कोई भी कार्यक्रम निःशुल्क आयोजित नहीं किया जा सकेगा और आयोजकों को नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन करके ही अनुमति प्राप्त करनी होगी।

उत्तराखंड के 8 शहरों में खुलेंगी 23 खेल अकादमी

न्यूज़ डेस्क

उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य के आठ शहरों में 23 खेल अकादमी खोलने का निर्णय लिया है। ये अकादमी खेल ट्रेनिंग के साथ 1300 करोड़ के खेल ढांचे की भी देखभाल करेंगी।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय खेलों के बाद एक लिगेसी योजना तैयार की गई है। इस योजना पर लगभग 33 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। प्रदेश की खेल लिगेसी नीति जल्द ही लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमी खेलेंगी, 23 विभिन्न खेलों के लिए अलग-अलग अकादमियों की स्थापना से राज्य से खिलाड़ियों का उत्कृष्ट विकास संभव होगा। खेल प्रशिक्षण के साथ-साथ 1300 करोड़ रुपये के खेल ढांचे की देखभाल भी अकादमी द्वारा की जाएगी। लिगेसी योजना के अंतर्गत 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए देश-विदेश से मंगाए गए लगभग 100 करोड़ रुपये के खेल उपकरणों की देखरेख की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, अकादमी के संचालन में संबंधित खेल संघों और फेडरेशनों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसमें शूटिंग, तैराकी, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, तीरंदाजी, आधुनिक पेंटाथलॉन, कुश्ती, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हैंडबॉल सहित 23 खेलों की अकादमियों की स्थापना का प्रस्ताव है।

ये 13 खेल अकादमी राज्य देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम और परेड ग्राउंड, हरिद्वार, पिथौरागढ़, हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के साथ ही उन सभी जगहों में खुलेंगी जहाँ पर राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिताएं पहले हुई है।

उत्तराखंड के आठ शहरों में 23 खेल अकादमी खोलने का निर्णय लिया है। ये अकादमी खेल ट्रेनिंग के साथ 1300 करोड़ के खेल ढांचे की भी देखभाल करेंगी।

उत्तराखंड के 8 शहरों में 23 खेलों के लिए अलग-अलग अकादमी खुलने से राज्य के खिलाड़ियों विकास होगा। अकादमी खुलने से खेल की सुविधाएं लंबे समय तक उपयोग में रहेंगी। ये 23 खेल अकादमी राज्य देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम और परेड ग्राउंड, हरिद्वार, पिथौरागढ़, हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के साथ ही उन सभी जगहों में खुलेंगी जहाँ पर राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिताएं पहले हुई है।

कौन होगा यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष?

ओबीसी दावेदारों की बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव, प्रदेश महामंत्री अमर पाल मौर्य, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और सांसद बाबू राम निषाद का नाम चर्चा में हैं। दलित चेहरों में पूर्व सांसद विनोद सोनकर, बसपा से आए जुगल किशोर और एमएलसी विद्या सागर सोनकर का नाम चर्चा में है।

न्यूज़ डेस्क

वैसे तो उत्तरप्रदेश में बीजेपी का सांगठनिक चुनाव पिछले साल से चल रहा है लेकिन अभी तक प्रदेश का अगला अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर तस्वीर साफ़ नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि आगामी यूपी चुनाव को देखते हुए पार्टी ऐसे किसी नेता की खोज कर रहे हैं जिनकी अगुवाई में पार्टी की जीत की संभव हो सके। बता दें कि बीजेपी ने पिछले दोनों चुनाव को ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में ही जीत पाई थी। 2017 में केशव प्रसाद मौर्या की अगुवाई में पार्टी को जीत मिली थी जबकि 2022 में स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में पार्टी को भारी जीत हासिल हुई थी। अब बीजेपी फिर से ऐसे नेता की खोज कर रही है जो पार्टी को जीत दिला सके।

प्रदेश अध्यक्ष के लिए दलित, ओबीसी और ब्राह्मण सभी वर्गों से दावेदारी हो रही है। ये दावेदार दिल्ली तक दौड़ भी लगा रहे हैं। अब ये केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि वह किस जाति का और मजबूत प्रदेश अध्यक्ष बनाए, जो जीत दिला सके। प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान पहले और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होगा। उससे पहले भाजपा चाहती है कि राष्ट्रीय संगठन और प्रदेश संगठन के साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकारों के बीच बेहतर तालमेल हो। यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन पर भी गंभीर मंथन चल रहा है।

इस समय जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नड्डा 2019 में पहली बार भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बने। उसके बाद 2020 में अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद से उनको बतौर अध्यक्ष एक्सटेंशन दिया जा रहा है। भाजपा में सामान्य तौर पर दो-दो साल के दो कार्यकाल तक लगातार अध्यक्ष रह सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि नड्डा की जगह किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पसंद रहे।

माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सहमति बन जाए तो उसके बाद प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया जाए। कहा जा रहा है कि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगड़ी जाति से होता है तो यूपी में भाजपा पिछड़े या दलित पर ही दांव लगाएगी। वैसे भी जिलाध्यक्षों के चुनाव में अगड़ों की संख्या पहले ही ज्यादा हो गई है। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी को बनाया जाता है तो यूपी में भाजपा किसी ब्राह्मण चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। इससे ब्राह्मणों की नाराजगी दूर की जा सकती है।

ओबीसी दावेदारों की बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव, प्रदेश महामंत्री अमर पाल मौर्य, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और सांसद बाबू राम निषाद का नाम चर्चा में हैं। दलित चेहरों में पूर्व सांसद विनोद सोनकर, बसपा से आए जुगल किशोर और एमएलसी विद्या सागर सोनकर का नाम चर्चा में है। ब्राह्मण चेहरे पर भाजपा दांव लगाती है तो फिर पूर्व डिप्टी सीएम डॉ दिनेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक और महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला का नाम चर्चा में है।

एचआईवी फंडिंग में कटौती से तीन मिलियन लोगों की मौत की संभावना

हेल्थ डेस्क

हालिया एक अध्ययन के अनुसार, एचआईवी रोकथाम और उपचार कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग में कटौती से 2030 तक 10 मिलियन से अधिक संक्रमण और लगभग तीन मिलियन मौतें हो सकती हैं। ये रिपोर्ट अभी लेसेन्ट पत्रिका में प्रकाशित हुई है। अध्ययन के अनुसार, एचआईवी रोकथाम और उपचार कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग में कटौती से 2030 तक 10 मिलियन से अधिक संक्रमण और लगभग तीन मिलियन मौतें हो सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बर्नेट इंस्टीट्यूट की एक टीम द्वारा किए गए अध्ययन में 2026 तक वैश्विक एचआईवी फंडिंग में अनुमानित 24 प्रतिशत की कमी के प्रभाव का मॉडल बनाया गया है। यह अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड सहित प्रमुख दाताओं द्वारा 8 से 70 प्रतिशत की सहायता कटौती की घोषणा के बाद हुआ है। ये पांच देश सामूहिक रूप से वैश्विक एचआईवी सहायता का 90 प्रतिशत से अधिक फंडिंग करते हैं।

शोधकर्ताओं ने कहा कि अगर अमेरिका और ब्रिटेन सहित शीर्ष पांच दाता देशों द्वारा प्रस्तावित फंडिंग कटौती को कम नहीं किया जाता है, तो अनुमान है कि 2025 और 2030 के बीच बच्चों और वयस्कों में 4.4 से 10.8 मिलियन अतिरिक्त नए एचआईवी संक्रमण और 770,000 से 2.9 मिलियन मौतें हो सकती हैं।

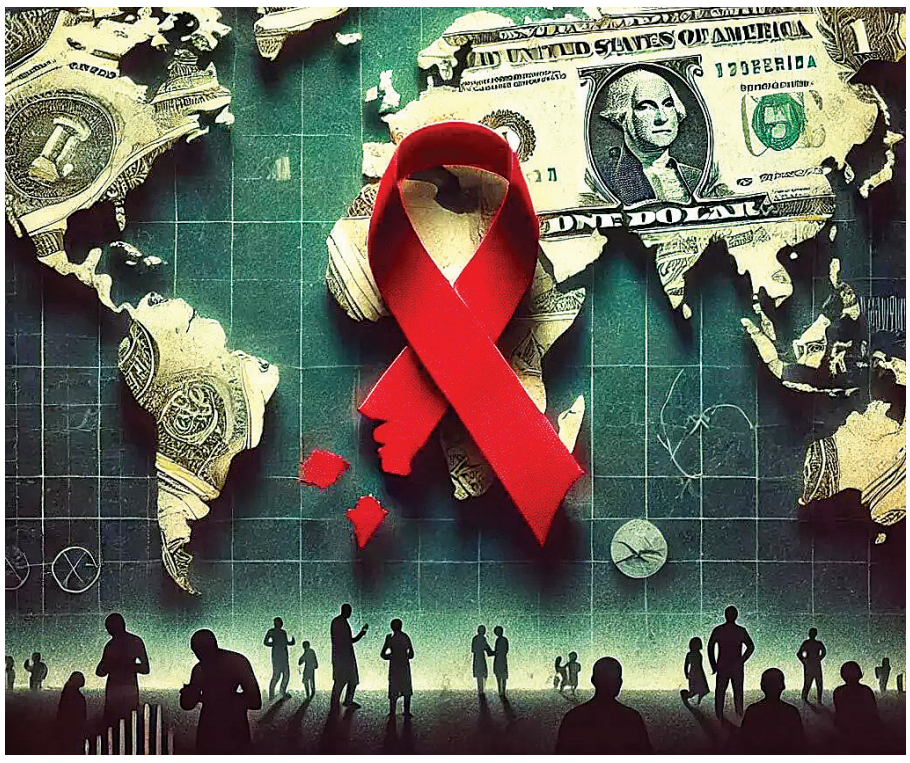

एचआईवी फंडिंग में दुनिया में सबसे अधिक योगदान देने वाले अमेरिका ने नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ ग्रहण के बाद 20 जनवरी को सभी सहायता रोक दी। अध्ययन में खुलासा किया गया है कि एड्स राहत के लिए राष्ट्रपति की आपातकालीन योजना (पीईपीएफएआर) के नुकसान के साथ-साथ अन्य फंडिंग कटौती के कारण अब 2030 तक वैश्विक स्वास्थ्य संकट के रूप में एचआईवी/एड्स को समाप्त करने की दिशा में प्रगति उलटने का खतरा है।

बर्नेट इंस्टीट्यूट की सह-अध्ययन लेखिका डॉ. डेबरा टेन ब्रिंक ने कहा, "अमेरिका ऐतिहासिक रूप से एचआईवी के उपचार और रोकथाम के वैश्विक प्रयासों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा है, लेकिन पीईपीएफएआर और यूएसएआईडी समर्थित कार्यक्रमों में मौजूदा कटौती ने पहले से ही एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी और एचआईवी की रोकथाम और परीक्षण सहित आवश्यक एचआईवी सेवाओं तक पहुंच को बाधित कर दिया है। आगे देखते हुए, यदि अन्य दाता देश फंडिंग कम करते हैं, तो एचआईवी के उपचार और रोकथाम के लिए दशकों की प्रगति बेकार हो सकती है." निष्कर्षों से पता चला कि उप-सहारा अफ्रीका और हाशिए पर रहने वाले समूह जो पहले से ही एचआईवी संक्रमण का सामना कर रहे हैं, जैसे कि ड्रग्स का इंजेक्शन लगाने वाले लोग, यौनकर्मी और पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष, साथ ही बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होंगे। संस्थान के सह-लेखक डॉ. रोवन मार्टिन-ह्यूजेस ने दिखाया कि परीक्षण और उपचार कार्यक्रमों को सीमित करने के अलावा, उप-सहारा अफ्रीका में व्यापक रोकथाम प्रयासों में कटौती देखी जाएगी, जैसे कि कंडोम वितरित करना और प्री-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (पीआरईपी - एक दवा, जो एचआईवी होने के जोखिम को कम करती है) की पेशकश करना।

शिलाजीत सेवन से पहले उसकी जांच जरूर करें

न्यूज़ डेस्क

शिलाजीत सबसे पावरफुल आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों में से एक है। सदियों से इसका इस्तेमाल पारंपरिक हर्बल दवाओं के तौर पर होता आ रहा है। यह एक ऐसा प्राकृतिक आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जो हिमालय, तिब्बत और अन्य पहाड़ी इलाकों में ही मिलती है। यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, खासतौर पर एनर्जी, स्टैमिना और पुरुषों की ताकत यानी मर्दानगी बढ़ाने के लिए। लेकिन बढ़ती मांग के कारण मार्केट में नकली शिलाजीत भी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि असली और नकली शिलाजीत की पहचान कैसे करें। यहां कुछ ऐसे टेस्ट जिनसे असली शिलाजीत का पता लगा सकते हैं।

कैसे करें असली शिलाजीत की पहचान

जब आप असली शिलाजीत को पानी में डालेंगे, तो यह पूरी तरह घुल जाएगा और पानी का रंग हल्का ब्राउन या गहरा भूरा हो जाएगा। यह पानी में किसी तरह की गंदगी या कण नहीं छोड़ेगा। वहीं, अगर शिलाजीत नकली है तो पानी में घुलने के बजाय नीचे बैठ सकता है या उसमें छोटे-छोटे टुकड़े रह सकते हैं। इसका रंग ज्यादा गहरा या काला भी हो सकता है।

असली शिलाजीत आग में जलाने पर पूरी तरह नहीं जलेगा। यह सिर्फ हल्का नरम हो जाएगा और उसमें से धुआं निकल सकता है। जबकि नकली शिलाजीत जल्दी जलने लगता है और इसमें से राख निकल सकती है। इससे प्लास्टिक जैसी गंध आ सकती है, जिससे पता चलता है कि इसमें केमिकल या मिलावट है।

असली शिलाजीत हाथ की गर्मी से नरम हो जाता है और आसानी से फैल जाता है। ठंडे मौसम में यह थोड़ा सख्त हो सकता है, लेकिन गर्म होते ही पिघलने लगेगा। जबकि नकली शिलाजीत सामान्य तापमान पर भी कठोर रह सकता है और आसानी से नहीं पिघलेगा।

स्टेंट की कीमतें बढ़ी, हार्ट बीमारी का इलाज हुआ महंगा

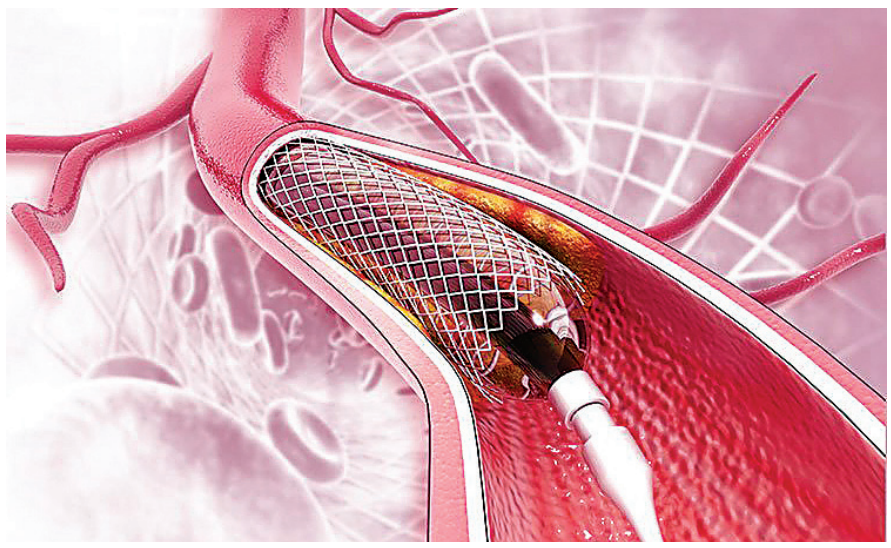

हेल्थ डेस्क

पहले इस आंकड़े को जान लीजिये। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, साल 2022 में 32,457 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई जो 2021 में दर्ज 28,413 मौतों की तुलना में 12.5% अधिक है। पिछले दो सालों में ये आंकड़े काफी बढ़ गए हैं। अब मुद्दे की बात। हार्ट रोगियों की मुश्किलें अब और बढ़ने जा रही है। क्योंकि हार्ट बीमारी का इलाज महँगा होने जा रहा है।शीर्ष दवा मूल्य नियामक नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ने कोरोनरी स्टेंट बनाने और आयात करने वाली कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला महंगाई में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि जिन कंपनियों के स्टेंट की खुदरा कीमत उसकी तय की गई अधिकतम सीमा से कम हैं, वे 2024 के थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार 1.74028% तक कीमतें बढ़ा सकती हैं।

इस बढ़ोतरी के साथ अब बेयर मेटल स्टेंट की अधिकतम कीमत 10,692.69 प्रति यूनिट हो जाएगी, जबकि ड्रग-एल्यूटिंग, बायोमेटैलिक और बायोरिज़ॉर्बेबल वैस्कुलर स्कैफोल्ड स्टेंट्स की अधिकतम कीमत 38,933.14 प्रति यूनिट तय की गई है। हालांकि, एनपीपीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो निर्माता तय की गई अधिकतम कीमत का पालन नहीं करेंगे, उन्हें ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त वसूली गई राशि के साथ ब्याज जमा करना होगा। एनपीपीए ने सभी रिटेलर्स और डीलर्स को निर्देश दिया है कि वे निर्माता द्वारा उपलब्ध कराई गई कीमत सूची को अपने व्यावसायिक स्थल पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। भारत में हृदय रोग का बढ़ता बोझ देखते हुए स्टेंट की अधिकतम कीमत में यह बढ़ोतरी अहम मानी जा रही है।

एनपीपीए ने रिंगर लैकटेट इंजेक्शन के कई यूनिट प्रकारों और पाइपरेसिलिन तथा ताजोबैक्टम के इंजेक्टेबल फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन की भी अधिकतम कीमतें तय की हैं। जहां रिंगर लैकटेट एक इंट्रावीनस सॉल्यूशन है जिसका इस्तेमाल शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी (जैसे डिहाइड्रेशन या ब्लड वॉल्यूम कम होने) की स्थिति में किया जाता है। वहीं पाइपरेसिलिन और ताजोबैक्टम का कॉम्बिनेशन निमोनिया जैसे बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज में उपयोग होता है।

काले धान की खेती से कर सकते हैं बंपर कमाई

कृषि डेस्क

अगर किसान काले धान की खेती शुरू करें तो उन्हें साधारण और बासमती चावल से ज्यादा फायदा हो सकता है। इसका मार्केट प्राइस भी ज्यादा होने से किसान इसकी खेती करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। बता दें कि बाजार में काले चावल का रेट कम से कम 500 रुपए प्रति किलोग्राम तक है। इसके अलावा काले धान की खूबी यह है कि इसका सेवन स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी लाभकारी है। इसमें साधारण धान की तुलना में कहीं अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं।

बाजार में कितना है काले धान का मूल्य

काले धान में पोषक तत्वों की मात्रा साधारण और बासमती चावल से अधिक होने के कारण इसकी बाजार मांग बढ़ी है। इससे इसकी बाजार में अच्छी कीमत मिल रही है। काले धान की कीमत 250 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति किलोग्राम तक है। जबकि साधारण व बासमती चावल की कीमत 30 रुपए किलोग्राम से लेकर 150 किलोग्राम तक होती है। वहीं हमारे देश से कुछ देशों जैसे-कतर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात में इसका निर्यात भी किया जाता रहा है।

काले धान की क्या है विशेषता

काले धान में एंटी-कैंसर एजेंट पाए जाते हैं। इसमें आयरन, फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा रहता है। ऐसे में बॉडी को फीट और स्वस्थ रखने के लिए काले चावल का सेवन काफी लाभकारी बताया जाता है।ब्लैक राइस को पकाने के बाद इसका रंग बदल जाता है, इसलिए इसे नीला भात भी कहा जाता है।इसके पौधे की लंबाई साधारण धान की तरह ही होती है लेकिन इसकी बाली के दाने लंबे होते हैं।काले धान की

फसल 100 से 110 दिन की अवधि में पककर तैयार हो जाती है।काले धान की खेती कम लागत और कम पानी में की जा सकती है। इसके पौधे मजबूत होते हैं जिससे पौधों के टूटने की समस्या नहीं होती है।

कहां से मिलेगा काले धान का बीज

कृषि विभाग और अन्य संस्थाएं एक वर्ष पहले भेजे गए मांग पत्र पर बीज उपलब्ध करा देती हैं। इसके अलावा काले धान का बीज कई ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म से भी खरीदा जा सकता है। वहीं किसान अपने क्षेत्र के काले धान के बीज उत्पादक किसान से भी इसके बीजों की खरीद कर सकते हैं।

कैसे करें काले धान की खेती

काले धान की खेती से पहले इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। किसान मानसून से पहले इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार होने में करीब एक माह का समय लगता है। काले धान की बीज की रोपाई के एक महीने बाद मुख्य खेत में पौधों की रोपाई की जाती है। इसकी फसल करीब 5 से 6 माह में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि अन्य किस्मों की तुलना में काले धान की फसल को तैयार होने में अधिक समय लगता है।

काले धान की किस्में

उड़ीसा राज्य में कलाबाती धान किस्म उगाई जाती है। धान की इस किस्म को क्षेत्रीय भाषा में किसान कालाबैंशी कहते हैं। यह किस्म पोषक तत्वों से भरपूर है। इस किस्म में एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं। कहा जाता है कि इस किस्म का चावल खाने से बुढ़ापा देरी से आता है यानि यह उम्र के बढ़ते प्रभाव को कम करने में सहायक है। उड़ीसा के अलावा मणिपुर और त्रिपुरा में भी इसकी खेती की जाती है। अब तो इसकी खेती अन्य राज्यों में भी होने लगी है जिनमें उत्तर प्रदेश,बिहार , मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं।

जलवायु परिवर्तन घट रही है फसलों की गुणवत्ता

कृषि डेस्क

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की मासिक बुलेटिन में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में अचानक आ रहे चरम बदलाव जैसे अत्यधिक या अपर्याप्त वर्षा फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। इससे कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है और फसलों की गुणवत्ता भी घट रही है। इस रिपोर्ट में खरीफ फसलों के उत्पादन पर अलग-अलग क्षेत्रों में वर्षा के असमान वितरण के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। बताया गया है कि किसी विशेष समय में अत्यधिक या कम वर्षा कैसे विभिन्न फसलों की उपज को प्रभावित करती है। फसल उत्पादन के लिए मौसमी घटनाओं का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर फसल का चक्र अलग होता है। उदाहरण के लिए जून और जुलाई में कम वर्षा होने से अनाज और दलहन उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि तिलहन फसलें कटाई के समय (अगस्त-सितंबर) में अधिक बारिश के कारण सबसे अधिक प्रभावित होती हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय खेती आज भी काफी हद तक मानसूनी बारिश पर निर्भर है। सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए विकसित किए गए नए बीजों के बावजूद मानसून की बारिश अब भी खेती की सफलता का अहम निर्धारक बनी हुई है। बारिश के पैटर्न में बदलाव, सूखा पड़ने या अत्यधिक वर्षा होने से फसलों की वृद्धि प्रभावित होती है और कीट व बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सामान्य या अच्छी वर्षा से खेती की उत्पादकता बढ़ती है, जबकि असमान वर्षा से कृषि क्षेत्र को गंभीर नुकसान उठाना पड़ता है।

यदि खरीफ की प्रमुख फसलों जैसे दलहन, तिलहन, चावल और मोटे अनाज के वार्षिक उत्पादन पर नजर डालें तो यह मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिम मानसून पर निर्भर करता है। जून और जुलाई में बारिश की मात्रा सोयाबीन, मक्का और दलहन की बुआई के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि इन महीनों में बारिश कम होती है तो उत्पादन प्रभावित होता है। इसी तरह जब कटाई का समय आता है तो अत्यधिक वर्षा होने पर तिलहन जैसी फसलें बुरी तरह प्रभावित होती हैं।

भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश

कृषि डेस्क

भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय निर्यात किया। इसके साथ ही श्रीलंका को पछाड़ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। इसी क्रम में केन्या ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।

भू-राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक बाजार में अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का चाय निर्यात 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम पर पहुंच गया, जो 10 साल का उच्चतम स्तर है। 2024 में देश के निर्यात में 2023 में दर्ज 231.69 मिलियन किलोग्राम

के इसी आंकड़े से 10 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि हुई।भारत के निर्यात का मूल्य 2023 के 6,161 करोड़ रुपये से 15 प्रतिशत बढ़कर 2024 में 7,111 करोड़ रुपये हो गया।

इराक को भेजे जाने वाले शिपमेंट में जोरदार वृद्धि हुई है, जो चाय निर्यात का 20 प्रतिशत है। इसी के साथ व्यापारियों को इस वित्त वर्ष में पश्चिम एशियाई देश को 40-50 मिलियन किलोग्राम चाय भेजने की उम्मीद है। भारतीय निर्यातक, जिन्होंने श्रीलंका की फसल कम होने पर पश्चिम एशिया के कई बाजारों में प्रवेश किया, वे वहां शिपमेंट की मात्रा को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। भारत 25 से अधिक देशों को चाय निर्यात करता है, जिसमें यूएई, इराक, ईरान, रूस, अमेरिका और यूके इसके प्रमुख बाजार हैं।

भारत दुनिया के शीर्ष पांच चाय निर्यातकों में से एक है, जो कुल विश्व निर्यात का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है। भारत की असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय दुनिया में सबसे बेहतरीन चाय में से एक मानी जाती है।भारत से निर्यात की जाने वाली अधिकांश चाय 'काली चाय' (ब्लैक टी) है, जो कुल निर्यात का लगभग 96 प्रतिशत हिस्सा बनाती है। अन्य किस्मों में नियमित चाय (रेगुलर टी), ग्रीन टी, हर्बल चाय, मसाला चाय और नींबू चाय (लेमन टी) शामिल हैं। भारत ने चाय उत्पादन को बढ़ावा देने, भारतीय चाय के लिए एक विशिष्ट ब्रांड बनाने और चाय उद्योग से जुड़े परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

असम घाटी और कछार असम के दो चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल में, दोआर्स, तराई और दार्जिलिंग तीन प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं।भारत का दक्षिणी भाग देश के कुल उत्पादन का लगभग 17 प्रतिशत उत्पादन करता है, जिसमें प्रमुख उत्पादक राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक हैं।छोटे चाय उत्पादक' भी कुल उत्पादन में लगभग 52 प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में सप्लाई चेन में लगभग 2.30 लाख छोटे चाय उत्पादक मौजूद हैं। भारत सरकार ने चाय बोर्ड के माध्यम से इस क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें 352 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), 440 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और 17 किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) का गठन शामिल है।गुणवत्तापूर्ण तुड़ाई, क्षमता निर्माण और फसल प्रबंधन के लिए एसटीजी के साथ बातचीत भी की जाती है।

इसके अलावा, प्रूनिंग मशीन और मैकेनिकल हार्वेस्टर की खरीद के लिए सहायता प्रदान की गई है। उद्यमियों और बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मिनी चाय फैक्ट्रियां भी स्थापित की गई हैं।भारतीय चाय उद्योग में 1.16 मिलियन कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं और इतने ही लोग अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए है।

डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी तो ईरान ने तैनात की मिसाइल

इंटरनेशनल डेस्क

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को धमकी दी है कि अगर वह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी समझौते पर नहीं पहुंचता तो अमेरिका उस पर बमबारी कर सकता है। ट्रम्प ने ईरान पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान भी आग बबूला हो गया है और उसने अमेरिका के खिलाफ मिसाइल से हमले की तैयारी कर दी है। बता दें कि पिछले दिनों ट्रंप ने एक समाचार चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर वे कोई डील नहीं करते हैं तो बमबारी होगी। यह ऐसी बमबारी होगी, जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी।ट्रम्प ने आगे कहा- उनके (ईरान) पास एक मौका है, अगर वे ऐसा नहीं करते तो मैं उनपर 4 साल पहले की तरह सेकेंडरी टैरिफ लगाऊंगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिकी और ईरानी अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया।

इस बीच ईरान की सेना ने किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया है।तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की मिसाइलें सभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में लॉन्चरों पर लोड कर दी गई हैं और लॉन्च के लिए तैयार हैं।तेहरान टाइम्स ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'पैंडोरा बॉक्स खोलने से अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।' आसान शब्दों में "पैंडोरा बॉक्स खोलना" का मतलब है किसी ऐसी चीज को शुरू करना, जिसके बाद बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाएं, और उन्हें रोकना मुश्किल हो। बता दें कि इससे पहले ट्रम्प ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान को सीधी बातचीत करने के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने रविवार को कहा कि वह अमेरिका के साथ सीधे तौर पर कोई समझौता नहीं करेगा।पजशकियान ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत की संभावना को हमने खारिज कर दिया गया है, लेकिन साफ नहीं है कि ट्रम्प अप्रत्यक्ष

बातचीत करने के लिए राजी होंगे या नहीं। 2018 में जब ट्रम्प ने ईरान के परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाला था, तब से अब तक की गई अप्रत्यक्ष बातचीत असफल रही हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रम्प ने 12 मार्च के यूएई के एक दूत के जरिए ईरान को चिट्ठी लिखी थी। इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नए सिरे से बातचीत करने के लिए न्योता दिया गया था।इसमें यह भी धमकी दी गई थी कि अगर ईरान वार्ता में शामिल नहीं होता है तो अमेरिका तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए कुछ करेगा।

इससे पहले ईरान ने 26 मार्च को अपनी तीसरी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया था। 85 सेकेंड के इस वीडियो में सुरंगों के भीतर मिसाइलें और आधुनिक हथियार दिखाई दे हैं। यह वीडियो ऐसे समय जारी किया गया है, जब डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को परमाणु प्रोग्राम खत्म करने की चेतावनी की डेडलाइन करीब है।ईरान के सरकारी मीडिया ने यह वीडियो जारी किया है। इसमें टॉप मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल मो. हुसैन बागरी और ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के एयरोस्पेस फोर्स के चीफ आमिर अली हाजीजादेह नजर आ रहे हैं।

वीडियो में दोनों अफसर सेना के वाहन पर सुरंगों के भीतर सफर कर रहे हैं और आसपास ईरान की आधुनिक मिसाइल और एडवांस वेपन दिखाई दे रही है। ईरान की सबसे खतरनाक खैबर शेकेन, कादर-एच , सेसिल और पावेह लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भी दिख रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हथियारों का इस्तेमाल हाल ही में इजराइल पर हमले में किया गया था।

ये दोनों देश झगड़ते क्यों रहते हैं?

1953 तख्तापलट : यह वो साल था, जब अमेरिका-ईरान के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख्तापलट करवाया। निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को हटाकर ईरान के शाह रजा पहलवी के हाथ में सत्ता दे दी गई। इसकी मुख्य वजह था-तेल। तेल के उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे।

1979 की ईरानी क्रांति : ईरान में एक नया नेता उभरा-आयतुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी। खुमैनी पश्चिमीकरण और अमेरिका पर ईरान की निर्भरता के सख्त खिलाफ थे। शाह पहलवी उनके निशाने पर थे। खुमैनी के नेतृत्व में ईरान में असंतोष उपजने लगा। शाह को ईरान छोड़ना पड़ा। 1 फरवरी 1979 को खुमैनी निर्वासन से लौट आए।

1979-81 की दूतावास संकट : ईरान और अमेरिका के राजनयिक संबंध खत्म हो चुके थे। तेहरान में ईरानी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास को अपने कब्जे में ले लिया। 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। 2012 में इस विषय पर हॉलीवुड फिल्म-आर्गो आई। इसी बीच इराक ने अमेरिका की मदद से ईरान पर हमला कर दिया। युद्ध आठ साल चला।

2015 - परमाणु समझौता : ओबामा के अमेरिकी राष्ट्रपति रहते समय दोनों देशों के संबंध थोड़ा सुधरने शुरू हुए। ईरान के साथ परमाणु समझौता हुआ, जिसमें ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की बात की। इसके बदले उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दी गई थी। लेकिन ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद यह समझौता रद्द कर दिया। दुश्मनी फिर शुरू हो गई। लेकिन अब मामला काफी आगे बढ़ता जा रहा है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान भी पूरी ताकत के साथ अमेरिका के साथ युद्ध करने को तैयार हो गया है। ईरान ने कहा है कि हमारी मिसाइल तैयार है और उनके निशाने पर दुनिया भर के अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं।

राजतंत्र की वापसी की मांग पर उबाल रहा नेपाल

इंटरनेशनल डेस्क

नेपाल को फिर से राजशाही चाहिए। पिछले कुछ महीनो से नेपाल के भीतर राजशाही समर्थक लोग सड़को पर उतर रहे हैं और नारे बाजी भी करते दिख रहे हैं। हालांकि पूरी नेपाल की जनता कुछ ऐसा ही सोंचती है ऐसा भी नहीं है लेकिन यह भी सच है कि पुराने राजशाही के समर्थक आज भी बड़ी संख्या में हैं और वे चाहते हैं कि नेपाल की सत्ता पर राजा की फिर से वापसी हो। मौजूदा समय में अभी यह सार्थक भले ही न लगे लेकिन जनता के सामने आज तक किसका चला है ? अगर नेपाल की जनता ऐसा ही सोचती है तो जाहिर हैं कि संघर्ष और भी तेज हो सकता है।

;पिछले दिनों नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीर लिए हजारों राजतंत्रवादी तिनकुने क्षेत्र में इकट्ठा हो गए। उन्होंने 'राजा आओ, देश बचाओ', 'भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद' और 'हमें राजतंत्र वापस चाहिए' जैसे नारे लगाए।काठमांडू में 28 मार्च को नेपाली सुरक्षाबलों और राजशाही समर्थक कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुईं। हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिससे शहर में अफरा-तफरी मच गई।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाईं, जिसके बाद कई घरों, अन्य इमारतों और वाहनों में आग लगा दी गई। हालात बिगड़ते देख कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार, स्थिति तब बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारियों ने निर्धारित सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की और पुलिस पर पत्थर फेंके। जवाब में, सुरक्षाबलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे।झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक व्यापारिक परिसर, एक शॉपिंग मॉल, एक राजनीतिक पार्टी मुख्यालय और एक मीडिया हाउस की इमारत में आग लगा दी, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और अन्य समूह भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

गौरतलब है कि नेपाल ने 2008 में संसदीय घोषणा के जरिए 240 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर दिया था। इससे देश राज्य एक धर्मनिरपेक्ष, संघीय, लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल गया।लेकिन बीते 19 फरवरी को लोकतंत्र दिवस पर प्रसारित एक वीडियो संदेश में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की

ओर से जनता से समर्थन की अपील के बाद राजशाही की बहाली की मांग फिर से उठने लगी ।इस महीने की शुरुआत में जब ज्ञानेंद्र देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक स्थलों का दौरा करने के बाद त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे, तो कई राजशाही समर्थक कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में एक रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों को 'राजा वापस आओ, देश बचाओ', 'हमें राजशाही चाहिए', और 'राजा के लिए शाही महल खाली करो' जैसे नारे लगाते हुए सुना गया।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नेपाल में राजशाही के पक्ष में इस भावना के पीछे एक प्रमुख कारण व्यापक भ्रष्टाचार और आर्थिक गिरावट से जनता की हताशा है। इसकी एक वजह शासन की स्थिति भी है। राजा को कभी शक्ति और स्थिरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, नेपाल ने 2008 में गणतंत्र में परिवर्तन के बाद से उस स्थिरता को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया है। पिछले 16 वर्षों में, देश ने 13 अलग-अलग सरकारें देखी हैं। अब नेपाल की राजनीतिक पार्टियां नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह को प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार मान रही है। सप्ताह देश में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के पीछे मुख्य सूत्रधार है। गणतंत्र समर्थक राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक में शाह पर यह आरोप लगाया गया। बैठक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से बुलाई गई थी।स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दलों ने पूर्व राजा पर संविधान को कमजोर करने और संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रणाली को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने का आरोप लगाया। गृह मंत्री रमेश लेखक ने कहा कि संविधान की रक्षा, राष्ट्रीय विकास और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के बीच एकजुट होने पर आम सहमति है।बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए लेखक ने कहा, "किसी भी संविधान विरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलग-अलग दलों के बीच विभिन्न मुद्दों पर असहमति के बावजूद, पूर्व पीएम बाबूराम भट्टाराई जो नेपाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, ने सुझाव दिया कि शाह के समर्थन में हाल ही में की गई गणतंत्र विरोधी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए उन्हें एकजुट होना चाहिए।" भट्टराई ने प्रेस से बात करते हुए कहा, "ज्ञानेंद्र शाह लंबे समय से ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि वे अभी भी राजा हों। राजनीतिक दलों और सरकार ने इसे दयापूर्वक अनदेखा किया है। हालांकि, 28 मार्च की घटना उनकी तरफ से उकसाई गई थी और यह एक आपराधिक कृत्य था। उनकी हरकतें अब सीमा पार कर गई हैं। इसीलिए मैंने सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव रखा है कि उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए।" इस बीच, संसद में चौथी और पांचवीं सबसे बड़ी पार्टियों राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को रविवार को सर्वदलीय बैठक से बाहर रखा गया। नेपाल के प्रमुख दैनिक काठमांडू पोस्ट के अनुसार, दोनों पार्टियों को गणतंत्र विरोधी ताकतें माना जाता है। ऐसे में नेपाल के बीच पूर्व राजा ,राजा समर्थक और लोकतांत्रिक पार्टियों के बीच अब एक अलग तरह की राजनीति होती दिख रही है। ऐसे में इस बात की सम्भावना बढ़ती जा रही है कि राजशाही समर्थक और राजनीतिक पार्टियों के बीच फासले बढ़ने की सम्भावना है और ऐसा होता है तो नेपाल के भीतर कई तरह के संघर्ष देखे जा सकते हैं।

बांग्लादेश में जारी हिंसक झड़प के मायने

इंटरनेशनल डेस्क

शेख हसीना की सरकार कब की चली गई। वे भारत में निर्वासित जीवन जी रही है। बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार भी चल रही है लेकिन बांग्लादेश आज भी शांत नहीं है। कभी वहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई होती है तो कभी दो दलों के बीच वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलती है। लेकिन इन सबके बीच वहां की आम जनता बेबस होकर सब कुछ देखने को मजबूर है। बांग्लादेश का आगे क्या होगा यह कोई नहीं जानता। अभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में दो प्रमुख राजनीतिक दलों - बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए। संघर्ष के दौरान कुल चार दुकानों में तोड़फोड़ की गई, पांच मोटरसाइकिलों और एक वैन को आग लगा दी गई।स्थानीय मीडिया के अनुसार, राजशाही के बाघा उपजिला के बाउसा यूनियन में यह संघर्ष हुआ। इसका कारण कमजोर समूह विकास कार्ड वितरित करने में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा था।

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हिंसा तब शुरू हुई जब बीएनपी की स्टूडेंट विंग, 'छात्र दल' के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर जमात की छात्र शाखा, 'इस्लामी छात्र शिबिर' पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में शिबिर कार्यकर्ताओं ने बाद में बीएनपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया।बांग्लादेश के प्रमुख अखबार 'द डेली स्टार' की रिपोर्ट के अनुसार, इन घटनाओं के बाद बीएनपी समर्थकों ने कथित तौर पर दुकानों में तोड़फोड़ की और जमात समर्थकों के वाहनों को आग लगा दी।बीएनपी और जमात दोनों ने ही झड़प की शुरुआत के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराया। पुलिस की मध्यस्थता से दोनों दलों के बीच हुए समझौते के बाद, जमात ने दावा किया कि बीएनपी समर्थकों ने उनके सदस्यों को निशाना बनाया, जिसमें 30 मार्च को एक छात्र नेता की हत्या का प्रयास भी शामिल है।इसके अलावा, जमात ने अपने कार्यकर्ताओं के घरों और व्यवसायों पर हमलों की रिपोर्ट की।

सलमान की फिल्म सिकंदर पायरेसी की शिकार

सलमान खान की सिकंदर फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है। बड़ी बात तो यह है कि पहले दिन ही इस फिल्म ने करीब 55 करोड़ की बिजनेस की है। अब हर दिन यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि सलमान खान की फिल्म रिलीज से पहले ही पायरेसी का शिकार हो गई थी। हालांकि इस पर तुरंत ही कार्रवाई हुई और अब इस फिल्म के सभी गैरकानूनी लिंक्स को इंटरनेट से हटा लिया गया। पिछले कुछ समय में इस तरह की घटनाएं कई बार सुनने को मिली हैं। फिल्म रिलीज से पहले या रिलीज के बाद इस तरह के पायरेसी फैलाने वाली वेबसाइट्स पर आ जाती है जो कि इसके बिजनेस के लिए बड़ा नुकसान भी साबित होता है। सिकंदर के केस में मामला तुरंत ही सामने आया और इस पर बहुत ही तेजी से एक्शन लिया गया। खैर , दुनियाभर में मिली इस फिल्म की ओपनिंग से ऐसा लग रहा है कि फैन्स को फिल्म पसंद आ रही है। इसकी ओपनिंग डे कलेक्शन को लेकर तमाम तरह की खबरें और अपडेट आ रही थीं हालांकि अब नाडियाडवाला ग्रैंडसन ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का आंकड़ा शेयर कर साफ कर दिया है कि पहले दिन का नंबर आखिर है कितना तो चलिए आपको भी बता ही देते हैं भाई को पहले दिन कितनी की ईदी मिली। प्रोडक्शन हाउस की लेटेस्ट पोस्ट के मुताबिक सिकंदर ने पहले दिन देशभर में 35.47 करोड़ की कलेक्शन की वहीं वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो देश के बाहर से सलमान खान को 19.25 करोड़ रुपये की ईदी मिली। इन दोनों नंबरों को अगर मिला लिया जाए तो सलमान खान की सिकंदर के खाते में पहले दिन 54.72 करोड़ रुपये आए हैं।

बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस लिस्ट में शामिल हुई कियारा

अभिनेत्री कियारा ने अपने करियर की शुरुआत 2014 में की थी और धीरे-धीरे अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर खुद को बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल कर लिया है।अपने अभिनय सफर में उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है, जिनमें कबीर सिंह, गुड न्यूज़, शेरशाह, जुग जुग जियो और सत्यप्रेम की कथा जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। उनकी हर फिल्म में उनके अभिनय को सराहा गया और उन्होंने हर बार खुद को एक बेहतरीन अदाकारा के रूप में साबित किया। उनके फैंस उनकी फिल्मों और उनके स्टाइल को लेकर हमेशा उत्साहित रहते हैं। फिलहाल कियारा अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पति और बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेग्नेंसी की खबर साझा की, जिससे उनके फैंस बेहद खुश हो गए।यह खुशखबरी शेयर करते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया, और फैंस से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के सितारों तक, सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।

कियारा की बढ़ती लोकप्रियता और फिल्मों की सक्सेस को देखते हुए, निर्माताओं ने भी उन्हें भारी भरकम रकम ऑफर करनी शुरू कर दी है। उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो कियारा जल्द ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं, जिनका उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।उनकी आने वाली फिल्मों में कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ उनकी जोड़ी देखने को मिलेगी, जो निश्चित रूप से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार कियारा आडवाणी ने हाल ही में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। अपनी दमदार एक्टिंग और लगातार हिट फिल्मों की बदौलत कियारा अब भारत की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गई हैं।रिपोर्ट्स के मुताबिक, कियारा जल्द ही कन्नड़ फिल्म 'टॉक्सिकः ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में नजर आएंगी, और इसके लिए उन्होंने तगड़ी रकम चार्ज की है। कियारा आडवाणी अब बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ इंडस्ट्री में भी अपनी जगह बनाने जा रही हैं। टॉक्सिक' में वह कन्नड़ सुपरस्टार यश के साथ नजर आएंगी, और इस फिल्म के लिए उन्होंने 15 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फीस ली है। इस रकम के साथ ही कियारा हाईएस्ट पेड बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गई हैं।

बॉलीवुड में भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार नहीं रहे

सिनेमा के दिग्गज एक्टर और फिल्म डायरेक्टर मनोज कुमार का निधन हो गया है। दिग्गज एक्टर ने 87 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। मनोज कुमार का निधन मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल हुआ। मनोज कुमार को खासतौर पर उनकी देशभक्ति के लिए जाना जाता था। इसके अलावा उन्हें 'भारत कुमार' के नाम से भी जाना जाता है। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 में पाकिस्तान में हुआ था।उनका असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था।मनोज कुमार एबटाबाद (अब पाकिस्तान) में पैदा हुए थे।देश के बंटवारे के वक्त उनका परिवार दिल्ली आ गया था।उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म शबनम में उनके किरदार मनोज कुमार के नाम पर अपना नाम रख लिया था। 24 जुलाई 1937 को जन्में मनोज कुमार ने देशभक्ति पर बनने वाली कई फिल्मों में एक्टिंग करने के साथ-साथ उन्हें डायरेक्ट भी किया था, जिनमें 'शहीद' (1965), 'उपकार' (1967), 'पूरब और पश्चिम' (1970), और 'रोटी कपड़ा और मकान' (1974) शामिल हैं। फिल्ममेकर अशोक पंडित ने मनोज कुमार के निधन पर शोक जताया है।उन्होंने कहा- मनोज कुमार, दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड विनर, हमारे इंस्पिरेशन और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के शेर थे।वो अब हमारे बीच नहीं रहे।ये हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान है।हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए मनोज कुमार को 1992 में पद्मश्री और 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

क्या आईपीएल 2025 से संन्यास लेंगे विराट?

खेल डेस्क

खबर आ रही है कि आईपीएल 2025 विराट कोहली संन्यास लेंगे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है अभी तक इसकी सही जानकारी नहीं मिली है लेकिन खेल जगत में कुछ यही सब कहा जा रहा है। बता दें कि विराट कोहली यानी किंग कोहली आईपीएल 2025 के बाद अपने संन्यास की घोषणा नहीं की है। विराट कोहली वर्तमान में आरसीबी के लिए एक अहम खिलाड़ी बने हुए हैं। उनका खेल अनुभव और कप्तानी कौशल टीम के युवा खिलाड़ियों के लिए बेहद प्रेरणादायक है। कोहली न केवल अपने बल्लेबाजी से बल्कि अपनी रणनीति और लीडरशिप से भी टीम को मजबूत बना रहे हैं।इस सीजन में वे कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड अपने नाम करने की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे उनके फैंस को उम्मीद है कि वे जल्द ही आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा कर सकते हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों की मानें तो विराट कोहली अभी भी बेहतरीन फॉर्म में हैं और उनमें खेल को और आगे ले जाने की क्षमता है।

उनके नाम पहले ही कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई मुकाम ऐसे हैं जिन्हें वे हासिल कर सकते हैं। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि वे आईपीएल 2025 के बाद संन्यास लेंगे। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे इस सीजन के बाद वाकई संन्यास का ऐलान करेंगे या यह सिर्फ एक अफवाह ही साबित होगी। आईपीएल 2025 के अंत तक इसका जवाब मिल ही जाएगा। टी20 क्रिकेट में 13,000 रन का लक्ष्यः विराट कोहली टी20 फॉर्मेट में अब तक कुल 12,886 रन बना चुके हैं। उन्हें 13,000 रन के आंकड़े तक पहुंचने के लिए केवल 114 रनों की आवश्यकता है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह पहले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे।सबसे अधिक फिफ्टी प्लस पारियांः विराट कोहली ने अब तक आईपीएल में 63 बार 50 या उससे अधिक रन बनाए हैं। डेविड वॉर्नर 66 फिफ्टी प्लस पारियों के साथ पहले स्थान पर हैं। इस सीजन में तीन और फिफ्टी प्लस पारियां खेलकर कोहली इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हैं।

टी20 में शतकों की संख्या बढ़ाने का अवसरः विराट कोहली के नाम टी20 क्रिकेट में 9 शतक हैं, जबकि बाबर आज़म के नाम 11 शतक हैं। इस सीजन में दो और शतक लगाकर कोहली बाबर के बराबर पहुंच सकते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत के बाद विराट कोहली न एक विशेष साक्षात्कार में अपने संन्यास और क्रिकेट के बाद की जिंदगी को लेकर खुलकर बात की।विराट ने स्पष्ट किया कि भले ही उनका क्रिकेट करियर शानदार रहा हो, लेकिन वह अपने जीवन के इस अध्याय को भी संतुलित तरीके से देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, "क्रिकेट मेरा जुनून है, लेकिन परिवार मेरी प्राथमिकता है। मैं अपनी जिंदगी के हर पल का आनंद लेना चाहता हूँ, चाहे वह मैदान पर हो या घर पर अनुष्का और बच्चों के साथ।" विराट ने यह भी बताया कि जब वे क्रिकेट से संन्यास लेंगे, तो वे अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट से दूरी बनाने का निर्णय आसान नहीं होगा, लेकिन यह उनके जीवन का एक स्वाभाविक पड़ाव है।

पत्रकारिता को नए सिरे से परिभाषित करते हुए न्यू देहली पोस्ट की शानदार प्रस्तुति अब आपके सामने है। इसमें होगी खोजी और जानबूझ कर दबाई गई ख़बरों के उद्भेदन की शानदार प्रस्तुति - न्यू दिल्ली पोस्ट प्रिंट और डिजिटल के सभी मंचो के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है :-

न्यू देहली पोस्ट
(साप्ताहिक हिंदी)

हमारे ये सभी डिजिटल मंच सभी सोशल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं। यहाँ जाकर आप ताजातरीन ख़बरों और विश्लेषण को देख समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं।

Website: https://newdelhipost.co.in/
: @NewDelhiPost
: https://www.facebook.com/NewDelhiPosts
: @NewDelhiPost
:newdelhipost_official

न्यू देहली पोस्ट
B-614, 6th Floor Tower B
Noida One Building
Noida Sector 62, Gautam Budh Nagar (UP)
Pin Code -201309

संपर्क करे - Email - postnewdelhi@gmail.com